RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

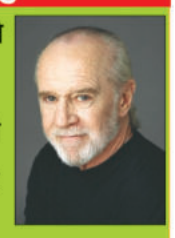

मुर्खों की ताकत को कभी भी हल्के में मत लो, विशेष रूप से तब जब वो समूह में हों।

जॉर्ज कॉर्लिन

वर्ष-08, अंक - 26 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 09 अप्रेल 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

फ्री बीज यानि रेवड़ियां कर्जा बढ़ा रही और शिक्षा, राशन के बजट में कटौती की जा रही है

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना नामक योजना की शुरुआत की थी। जिसमें 18 से 60 वर्ष तक की प्रत्येक महिलाओं को 1000 रूपए प्रति माह राज्य सरकार द्वारा दिया गया। जो बाद में 1250 और फिर 1500 रूपए हुए। इस योजना को विधानसभा में भाजपा का मास्टर स्टॉक कहा गया और चुनाव परिणामों ने इसे सही भी साबित किया। भाजपा ने ऐतिहासिक रूप से सत्ता में वापसी की। जिसके बाद चुनाव पंडितों ने इसे एंटी इनकम्बेसी के काट के रूप में प्रो इनकम्बेसी बताया और देखते ही देखते इस प्रकार की योजनाएं अन्य चुनावी राज्यों में भी लागू होने लगी। जिसके बाद देशभर में यह चर्चा का विषय है कि, ये इस प्रकार की फ्री बीज योजनाए भले ही तात्कालिक चुनावी लाभ के लिए अपनाई जा रही है। लेकिन ये अन्ततः देश के भविष्य के लिए हानिकारक ही है। हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए युवा विधायक सम्मेलन में यह बात निकलकर सामने आई। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी के लिए युवा विधायको की जिम्मेदारी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में युवा विधायकों की भूमिका पर केंद्रीय इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे के बयानो ने यह नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने जहां राजनीतिक वंशवाद की बात कही। वहीं कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे ने देशभर में फ्री बीज योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। एक और जहां वंशवाद पर भाजपा स्पष्ट मत रखती है लेकिन वह भी इससे अछूती नहीं है। वही मुफ्त की योजनाओं फ्री बीज के बारे में लगभग सभी राजनीतिक दल किनारा करते रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्यों तक विपक्षी दल भी इस पर सवाल नहीं उठाते हैं क्योंकि वे भी इसी भरोसे चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्ति की संभावना को देखते हैं। कांग्रेसी विधायक हेमंत कटारे ने अपनी पार्टी की गाइडलाइन से परे मुक्त की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि, महिलाओं को हर माह नगद राशि देने से उनका सशक्तिकरण संभव नहीं है। बल्कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और यह राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए भी ठीक नहीं हैं। अगर राजनीतिक दल वास्तव में चाहते हैं कि, महिलाएं सशक्त हो तो उन्हें रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी मुफ्त की योजनाओं को लेकर अधिक धनराशि के कई वादे किए थे, हालांकि कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन विभिन्न प्रदेशों के चुनाव में लगभग सभी पार्टियों इन फ्री बीज योजनाओं की घोषणा करती रही है।

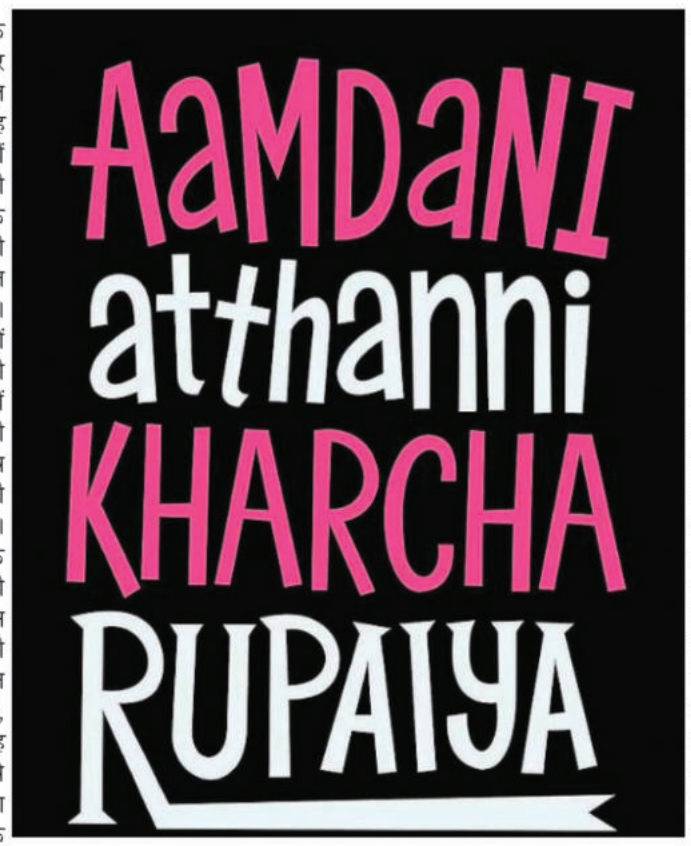

अब ये योजनाए राज्यों के लिए बड़ा बोझ बनती जा रही है। हालत ये बनते जा रहे हैं कि, इनको पूरा करने के लिए राज्य न तो संसाधन जुटा पा रहे हैं और न ही संतुलित बजट बना पा रहे हैं।

कुछ राज्यों में तो इन घोषणाओं का बोझ 30 से 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है। हिमाचल जैसे छोटे राज्यों में नगदी संकट की विकट स्थिति है।

हाल ही में राज्य के सीएम, मंत्री, विधायको समेत वरिष्ठ अफसरो के वेतन-पेंशन टालने पड़े और बजट के आकार को कम करना पड़ा।

फ्री की योजना का यह असर

मप्र में लाड़ली बहना योजना के चलते जीएसडीपी के मुकाबले कर्ज 32 प्रतिशत पहुंच गया। महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के दबाव के कारण त्योहारों में मिलने वाली राशन किट योजना बंद कर दी गई है। पंजाब में डीए एरियर 12 साल से लंबित है। तेलंगाना को चुनावी घोषणाओं के लिए हर साल 1 लाख करोड़ रु. चाहिए, लेकिन बजट की कमी से कई योजनाएं अटकी हैं।

1 लाख करोड़ का कर्ज

एक समाचार पत्र अनुसार हिमाचल पर 2023 में 86 हजार करोड़ का कर्ज था। कांग्रेस ओपीएस, महिलाओं को कैश, मुफ्त बिजली जैसे वादों के साथ चुनाव जीती थी। इनका बोझ कुल राजस्व का करीब 29 प्रतिशत था। राज्य की आय 38 हजार करोड़ थी, जिसमें 60 प्रतिशत वेतन, पेंशन, ब्याज में खर्च होता था। ओपीएस के बाद यह 75 प्रतिशत हो गया। दो साल में करीब 14 हजार करोड़ कर्ज लिया, जिससे कुल कर्ज 1 लाख करोड़ पहुंच गया है।

आमदनी अठन्नी खर्चा रूपया

मप्र में, लाड़ली बहना, मुफ्त सिलेंडर और बिजली सब्सिडी पर ही सालान करीब 50 हजार करोड़ का खर्च हो रहा है।

तेलंगाना में, नौ चुनावी वादों में छह लागू। इन पर 50,713 करोड़ रूपए का सालाना खर्च, बाकी योजनाओं के लिए 40 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है।

झारखंड में, सालाना 14,065 करोड़ रूपए की मंईया सम्मान योजना। चुनावी वादो का सालाना खर्च 40 हजार करोड रूपए।

बिहार में, महिलाओं को कैश ट्रांसफर और सब्सिडी पर 40 हजार करोड़ सालाना खर्च। कुल कर्ज 37 प्रतिशत तक।

महाराष्ट्र में, राज्य का सब्सिडी बिल 60 हजार करोड़ तक पहुंचा। 'शिव थाली' योजना का बजट आधा किया। इसमें 10 रूपए में भरपेट भोजन मिलता है।

राजस्थान में, सड़क, पानी पर होने वाला खर्च का बजट 28 प्रतिशत तक कम किया। मुफ्त सेनेटरी पैड मिलना बंद।

कर्नाटक में, छह गारंटी योजनाओं पर 50 हजार करोड़ रूपए सालाना खर्च; अभी युवा निधि देने को लेकर भी दबाव।

पंजाब में, राजस्व प्राप्त 1.26 लाख करोड़। योजनाएं 2.6 लाख करोड का। वेतन-पेंशन, ब्याज पर 90 हजार करोड़ रूपए।

इस तरह से राज्यो की स्थिति आमदनी अठन्नी की है और खर्चा रूपया का है।

सीजफायरः ईरान में भारतीयों को दूतावास की चेतावनी, देश छोड़ने की सलाह

तेहरान।

ईरान में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए नई चेतावनी जारी की है। युद्ध विराम लागू होने के कुछ घंटों बाद जारी परामर्श में कहा गया है कि, ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक जल्द से जल्द देश छोड़ दें और दूतावास द्वारा बताए गए सुरक्षित मार्गों का ही उपयोग करें। यह सलाह 7 अप्रैल 2026 को जारी पूर्व परामर्श का विस्तार है।

दूतावास ने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की ओर जाने से पहले उससे संपर्क करने की बात कही है। इससे पहले जारी निर्देशों में नागरिकों को 48 घंटे तक सुरक्षित स्थानों पर रहने, बिजली और सैन्य ठिकानों से दूर रहने तथा बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से बचने की सलाह दी गई थी। होटलों में ठहरे लोगों को अपने कमरों में रहने और दूतावास से लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान के ठिकानों पर हमले के बाद तनाव की स्थिति बनी थी। उस समय ईरान में लगभग 9 हजार भारतीय नागरिक मौजूद थे, जिनमें अधिकांश विद्यार्थी हैं।

अब तक करीब 1800 भारतीय सुरक्षित रूप से वापस लौट चुके हैं। दूतावास ने नागरिकों से आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखने और जोखिम वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है।

किडनी प्रकरणः शिकायतकर्ता ही जांच के घेरे में

कानपुर।

शहर के चर्चित किडनी प्रत्यारोपण प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। अब तक खुद को पीड़ित और मजबूर दाता बताने वाले आयुष चौधरी पर ही पुलिस की जांच केंद्रित हो गई है। उसके दावों और पृष्ठभूमि में सामने आई विसंगतियों के बाद पुलिस ने जांच की दिशा बदल दी है और अब यह पता लगाया जा रहा है कि वह वास्तव में पीड़ित है या पूरे मामले का अहम हिस्सा।

जांच के दौरान पुलिस को आयुष से जुड़ी कई संदिग्ध जानकारियां मिली हैं। प्रारंभिक पूछताछ में उसने खुद को उत्तराखंड का छात्र बताया था, लेकिन अब उसके बिहार से जुड़े होने के प्रमाण सामने आए हैं। इसके अलावा जांच एजेंसियां उसके संभावित साइबर ठगी से जुड़े संबंधों की भी जांच कर रही हैं।

पुलिस को आयुष से जुड़े करीब 16 परिचितों की सूची मिली है, जिनके दूरभाष अभिलेख, आर्थिक लेनदेन और आपसी संबंधों की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच का दायरउत्तराखंड और बिहार के साथ अन्य राज्यों तक भी बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस गुजरात पुलिस से भी संपर्क की तैयारी में है।

आशंका जताई जा रही है कि आयुष के संबंध किसी बड़े अंतरराज्यीय साइबर या आर्थिक अपराध गिरोह से हो सकते हैं। इन संपर्कों से पूछताछ के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

फिलहाल पुलिस ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन तेज जांच से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकते हैं। किडनी प्रत्यारोपण का यह मामला अब केवल अस्पतालों और बिचौलियों तक सीमित न रहकर एक बड़े संगठित आपराधिक तंत्र से जुड़ता नजर आ रहा है।

तमिलनाडु चुनाव, तेज हुआ प्रचार, गठबंधन पर सवाल

चेन्नई। तमिलनाडु में चुनावी माहौल चरम पर पहुंच गया है और सभी प्रमुख दल मतदाताओं को आकर्षित करने में जुटे हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सक्रियता को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में लगातार दौरे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राज्य में अब तक सीमित मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

पिछले दो महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं और सहयोगी दलों के समर्थन में जनसभाएं कर चुके हैं। उनका यह प्रचार अभियान आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि 15 अप्रैल को वे नागरकोइल में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे।इसके विपरीत राहुल गांधी ने अभी तक तमिलनाडु में कोई सभा नहीं की है, जिससे कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच

तालमेल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसकी तुलना वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव से कर रहे हैं, जब राहुल गांधी ने पहले ही चरण में सक्रिय प्रचार शुरू कर दिया था।

हाल ही में पुडुचेरी में दोनों दलों के बीच दूरी के संकेत भी देखने को मिले। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में सहयोगी दल का उल्लेख नहीं किया, वहीं एम. के. स्टालिन ने भी अपने भाषण में राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया। दोनों नेताओं के कार्यक्रम भी अलग-अलग समय पर आयोजित किए गए, जिससे उनका आमना-सामना नहीं हो सका।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह स्थिति सीट बंटवारे को लेकर हुए मतभेदों का परिणाम हो सकती है। हालांकि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि कार्यक्रमों में बदलाव संभव नहीं था और दोनों नेता जल्द ही एक साथ नजर आएंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी 10 अप्रैल के बाद तमिलनाडु में प्रचार अभियान शुरू कर सकते हैं।

बाला बच्चन का आरोपः खरीद-फरोख्त से बनी भाजपा सरकार

माही की गूंज, बड़वानी।

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के पूर्व गृहमंत्री एवं राजपुर विधायक बाला बच्चन ने बुधवार को बड़वानी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस को राज्यसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए षड्यंत्र कर रही है।

बाला बच्चन ने आरोप लगाया कि भाजपा पूर्व में भी विधायकों की खरीद-फरोख्त कर सरकारें बना चुकी है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में भी 27 विधायकों की खरीद-फरोख्त कर सरकार बनाई गई थी और इसी प्रकार के प्रयोग अन्य राज्यों में भी किए गए हैं। उन्होंने भाजपा पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया।

पूर्व गृहमंत्री ने राज्यसभा चुनाव में संभावित 'घोड़ों की खरीद-फरोख्त' की आशंका भी जताई। उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को इस प्रकार की आशंका संबंधी जानकारी मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस द्वारा घोषित प्रत्याशी के समर्थन में सभी विधायक मतदान करेंगे और उसे विजयी बनाने के लिए पूरी तरह सक्रिय रहेंगे।

बाला बच्चन ने कहा कि बड़वानी जिले के कांग्रेस के तीनों विधायक पूरी तरह सतर्क हैं और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव प्रक्रिया में सजग है और अपने विधायकों को राज्यसभा भेजने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री के सम्मान में डोभाल का रात्रिभोज

नई दिल्ली।

भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ समय से चली आ रही ठंडक अब धीरे-धीरे कम होती दिखाई दे रही है। हाल ही में हुई कूटनीतिक गतिविधियां दोनों देशों के संबंधों में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रही हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अपने आवास पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के सम्मान में विशेष रात्रिभोज आयोजित किया।

यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे दोनों देशों के संबंधों में नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेशी विदेश मंत्री का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद किसी वरिष्ठ मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। तीन दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में आई दूरी को कम करने और सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा हुई।

पिछले वर्ष अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने और उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। कई महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद लगभग रुक गया था, लेकिन अब नई सरकार और हालिया प्रयासों के चलते माहौल में सुधार देखा जा रहा है।इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी प्रस्तावित है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली, व्यापार बढ़ाने और लंबित मुद्दों के समाधान पर चर्चा होने की संभावना है। गंगा जल बंटवारा समझौता, ऊर्जा सहयोग और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल रह सकते हैं।

बांग्लादेश ने भारत से अतिरिक्त डीजल और पेट्रोल आपूर्ति की मांग भी रखी है। साथ ही वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों और व्यापारियों के बीच आवागमन सुगम हो सके।

एक संवेदनशील मुद्दा शेख हसीना का भारत में रहना भी बना हुआ है। अगस्त 2024 के बाद से वे भारत में हैं और बांग्लादेश की नई सरकार उनकी वापसी की मांग कर रही है, हालांकि भारत ने इस विषय पर अभी तक कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है।

इस बीच एक सकारात्मक संकेत यह भी सामने आया है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपने क्षेत्र के पांच मंदिरों के लिए 6.5 करोड़ टका की सहायता देने की घोषणा की है। इसे भारत के लिए एक भरोसेमंद संदेश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भारत हमेशा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है।

आखिर समाज में हमारे बीच कितनी बेवफा सोनम

घड़ियाली आंसू बहाने वाली प्रियंका निकली पति की हत्यारी, 1 लाख की दी थी सुपारी

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

धार। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या नवविवाहिता सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। जो घटना पूरे देश में रूह कपाने वाली सामने आई थी। जिसके बाद ऐसे कई मामले सामने आने लगे जिसमें पत्नी ही अपने साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या करती है।

ऐसे ही एक चौंकाने वाली घटना धार जिले के सरदारपुर थाना क्षेत्र के गोंदी खेड़ा चारण में सामने आया। मामला 6-7 अप्रैल की रात्रि का है। जिसमें पति देवकृष्ण पुरोहित (मिर्ची व्यापारी) की हत्या के बाद पत्नी प्रियंका अपने घडियाली आंसू बहाकर पति की हत्या का दुख जता रही थी। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर हो पर अपना गुनाह कहीं न कहीं बयां कर ही देता है।

उक्त घटना में सामने आ रहा है कि, पत्नी ने अपने प्रेमी एवं उसके साथी के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचा और रात्रि में हत्यारे सुनियोजित षड्यंत्र के साथ हथियार लेस घर के अंदर घुसे और पति की हत्या कर रफु-चक्कर हो गए। षड्यंत्र के साथ ऐसा

दर्शाया गया कि, बदमाश लूट की नीयत से घर में घुसे और महिला को अलग कमरे में बंधक बनाया। तथा तीन लाख के जेवराज व 50 हजार रुपए नगदी की लूट की घटना का अंजाम बताया। पत्नी प्रियंका (27) रोते हुए अपने बयानों पर तटस्थ नहीं रह पाई और बदलते बयानों के साथ पुलिस को शंका होने पर पत्नी के आवभाव को भी जांच में जानने का प्रयास किया। तथा जिस तरह से अपराधियों ने उसे बंधक बनाया बताया तथा हाथ की चोट विपरीत दिशा में बयां कर रही थी।

एसपी मयंक अवस्थी के नेतृत्व में गंभीरता के साथ जांच करने पर सामने आया कि, जिस जेवरात को लूट होना बता रहे थे वह जेवरात घर के अंदर ही पाए गए। जिसके बाद पुलिस ने महिला से पूछताछ करने पर सामने आया कि, प्रियंका पुरोहित अपने ही पति के परिवार के कमलेश पुरोहित (33) से प्रेम करती थी और उसके साथ मिलकर पति की हत्या का षड्यंत्र रचा।

कमलेश पुरोहित ने सुपारी लेने वाले आरोपी सुरेंद्र पिता प्रतापसिंह से संपर्क किया और 1 लाख रुपए में हत्या करने की सुपारी दी। इस तरह से पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने बेवफा पत्नी प्रियंका व कमलेश पुरोहित को गिरफ्तार कर लियां। जबकि सुपारी लेने वाला सुरेंद्र प्रतापसिंह फरार है।

उक्त देवकृष्ण पुरोहित की हत्या के खुलासे के बाद लोगों के जहन में यही विचार आ रहा है कि, जिस पत्नी की खुशियों के लिए पति दिन-रात मेहनत करता है और हर सुख देने का प्रयास करता है, वही पत्नियां अपने आशिकाना के चलते पतियों की हत्याए कर रही है। ऐसी हत्यारी और कितनी प्रियंका, सोनम बनकर हमारे समाज में हमारे बीच रहकर षड्यंत्र रच रही है। ऐसी षड्यंत्रकर्ता महिलाओं को समाज में जीने का हक नहीं है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाकर ऐसे अपराधों में जल्द से जल्द फांसी की सजा ऐसी षडयंत्र कारी सोनम के विरुद्ध होनी चाहिए। ताकि भविष्य में इस तरह की अमानवीय घटनाएं हमारे समाज में सामने न आए।

कलश यात्रा के साथ हुआ भागवत कथा का शुभारंभ

माही की गूंज, बरवेट/पेटलावद।

पारंपरिक वेश में बुधवार से ग्राम बरवेट के पूर्व दिशा में स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। श्री कुंज आश्रम उज्जैन की साध्वी श्री सुगना बाईसा के नेतृत्व में प्राचीन शंकर मंदिर से पवित्र जलस्त्रोत से जल भरने के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल रहीं। पवित्र जलस्त्रोत से कलश को भर कर लाने के बाद कथा स्थल पर धार्मिक विधि एवं मंत्रोच्चरण के साथ स्थापित किया गया। आरती के साथ शुरू किए गए श्रीमद् भागवत कथा का श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम इसकी महिमा से अवगत कराया। व्यास पीठ से कथा व्यास साध्वी श्री सुगणा बाईसा ने श्रीमद् भागवत का अर्थ बताते हुए कहा कि, भगवान श्री कृष्ण (विष्णु) से संबंधित पावन कथा, जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य प्रदान करती है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भक्ति का अमृत है, जिसे सुनकर मन शुद्ध होता है, अहंकार नष्ट होता है और ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होता है। 'भागवत' शब्द भक्ति (भ), ज्ञान (ग), वैराग्य (व) और तत्व/त्याग (त) का संगम है। उन्होंने बताया कि, विश्व में सभी कथाओं में ये श्रेष्ठ मानी गई है। जिस स्थान पर इस कथा का आयोजन होता है, वो तीर्थ स्थल कहलाता है। इसको सुनने एवं आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियां को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा अन्य भी इसे गलती से भी श्रवण कर लेता है, तो भी वो कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए सात दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई सात दिन तक किसी व्यवस्तता के कारण नहीं सुन सकता है, तो वह दो तीन या चार दिन ही इसे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकालें। तब भी वो इसका फल प्राप्त करता है। क्योंकि ये कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, जिसमें उनके अवतार से लेकर कंस वध का प्रसंग का उल्लेख होने के साथ-साथ इसकी व्यक्ति के जीवन में महत्ता के बारे में भी बताया गया है। इसके सुनने के प्रभाव से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ-साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। साध्वी श्री ने बताया कि, इस कथा को सबसे पहले अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने सुना था, जिसके प्रभाव से उसके अंदर तक्षक नामक नाग के काटने से होने वाली मृत्यु का भय दूर हुआ और उसने मोक्ष को प्राप्त किया था। आज की आरती और प्रसादी का लाभ निलेश पटेल परिवार ने लिया। कथा में भजनों पर श्रद्धालुओं ने खूब नृत्य किया।

टेबलेट में दर्ज हुइ जिले के विद्यालयों के बच्चों की दक्षताएं

माही की गूंज, बरवेट।

परख एनसीईआरटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर सर्वे में पहली बार पूरे देश में एक ही तिथि में एक साथ सर्वे के माध्यम से कक्षा तीसरी के बच्चों की भाषा एवं गणित की दक्षताओं का आकलन, मूल्यांकन, नियमों व गोपनियता का ध्यान रखते हुए किया गया। बच्चों की दक्षताओं की जांच के साथ-साथ विद्यालय के प्रभारी एवं भाषा एवं गणित के शिक्षकों की जानकारी भी टैबलेट के माध्यम से छात्राध्यापक, छात्रध्यापिकाओं ने दर्ज की। जिले की कुल 21 शालाओ का चयन हुआ। जिसमें शासकीय-अशासकीय हिंदी एवं अंग्रेजी दोनो माध्यम की

शालाएं रही। एफएसएल के मास्टर ट्रेनर लोकेंद्र बैरागी ने बताया कि, इस सर्वे में जिले के पेटलावद ब्लाक की नवापाड़ा प्राथमिक विद्यालय भी शामिल हुई। ग्रामीण अंचल में सर्वे के लिए जाने वाले एफआई को आवागमन सहयोग के लिए डाइट के माध्यम से डीआरजी प्रशिक्षकों का सहयोग दिया गया। सर्वे के दौरान जमीनी स्तर पर सहयोग के दृष्टिकोण व व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिले के डीपीसी डाइट प्रिंसिपल, जिला प्रोग्रामर एपीसी एकेडमी द्वारा अवलोकन किया गया। कलेक्टर एवं सीईओ के मार्गदर्शन में उक्त सर्वे कार्य दो दिवस तक जिले में किया जाना है।

जिले भर के शिक्षकों ने रैली निकालकर सौपा ज्ञापन

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले में शिक्षको ने लामबंद्ध होकर सरकार के विरूद्ध अपना मोर्चा खोल दिया है। अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा बुधवार को टीटीई निर्णय पर पुनर्विचार याचिका लगाने व पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर डॉ.भीमराव अंबेडकर पार्क में धरना दिया। उसके बाद एक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम महेश मंडलोई को ज्ञापन सौंपा ।

पिछले कई दिनों से संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश संगठन के आह्वान पर आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही थी। बुधवार को सुबह 11 बजे से जिले के विभिन्न शिक्षक डॉ.अंबेडकर पार्क में एकत्रित होने लगे थे। दोपहर 12 बजे से धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया।

कई संगठनों के पदाधिकारियों में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर संबोधित किया। शिक्षकों का कहना था कि, शिक्षक ईमानदारी से अपना कार्य करते है। शिक्षा के अलावा अन्य सौंपे गए दायित्वों का भी निर्वाहन समय सीमा में करते रहे है, उनके समक्ष कई समस्याएं खड़ी है जिनका निराकरण जरूरी है।

गंभीर संकट उत्पन्न

सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि, निर्णय के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक प्रायमरी एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए नियुक्ति तिथि से जो भी हो रही हो शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटीई को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षकों की आजीविका व पदोन्नति पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा एनसीटीई अधिसूचना 23 अगस्त 2010 अंतर्गत वर्ष 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधि रूप से क्वालीफाइड की श्रणी में रखा गया था। जबकि 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए निर्धारित अवधि में टीटीई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था। ज्ञापन में कहा गया कि, नवीन निर्णय में उन दोनों श्रेणियों के मध्य स्पष्ट विधिक अंतर की अपेक्षा की गई है। साथ ही तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न वर्षों में क्रियान्वयन हुआ है। जिसके कारण टेट की बाध्यता प्रभावी तिथि भी अलग-अलग राज्यों में जारी राजपत्रों, नोडल एजेंसियों की अधिसूचना के अनुसार अलग है। मध्यप्रदेश में पात्रता परीक्षा की बाध्यता प्रभावी तिथि 26 मार्च 2011 है। वर्तमान में न्यायिक निर्णय इन सभी वैद्यानिक एवं प्रशासनिक भेदों की उपेक्षा कर दी है। इस कारण राज्य द्वारा जारी टेट परीक्षा की प्रथम अधिसूचना के पूर्व विधि पूर्वक नियुक्त शिक्षकों को क्वालीफाइड का दर्जा संकट में आ गया है। जिससे वे तनाव में है। ज्ञापन में तीन अन्य मांगे भी रखी गई।

सरकार के सामने स्वास्थ्य का संकट

प्रदेश में चिकित्सकों की कमी और प्रदेशभर में लग रही झोलाछापो की लंबी कतार

माही की गूंज, झाबुआ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, और स्वच्छता सभी के आवश्यक है, जिस स्थान, समाज, या राज्य में इन तीनों की स्थिति दयनीय होगी वहां के विकास में बाधाएं और समस्याएं बरकरार रहेगी, इसीलिए मुखिया को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके कार्य क्षेत्र में स्वच्छता रहे और इसी तरह मुखिया के राज्य में सभी को शिक्षा प्राप्त होती रहे और सभी नागरिको को बिना देरी किए सही समय पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए। मगर मध्यप्रदेश में देखा जाए तो तीनों की स्थिति दयनीय दिखाई देती है। मुख्य-मुख्य शहरो में मुख्य-मुख्य मार्गों पर स्वच्छता दिखाई देती है, शिक्षा में अभी भी नई पौध का पल्लव ना के बराबर है। शाला त्यागी बच्चें शाला पहुंचने में संपर्क से बाहर है। प्रदेश के स्वास्थ्य को लेकर अनेक चिंता की लकीरे माथे पर रहती है मगर मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र के विकास में व्यस्त भारी पलकों को इस तरफ उठाने असमर्थ दिखाई देते हैं।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जारी रिपोर्ट के माध्यम से देखा जाए तो प्रदेश में 1836 लोगों पर एक एलोपैथी डॉक्टर मौजुद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुरुप एक हजार जनसंख्या पर एक एलोपैथी डॉक्टर होना चाहिए परंतु मध्य प्रदेश में स्थिति कुछ और है। सरकारी और नीजी चिकित्सक मिलाकर 49 हजार डॉक्टर प्रदेश में विद्यमान है और जनगणना निर्देशालय के अनुसार मध्यप्रदेश की अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2026 में 9 करोड़ के आसपास होगी। इसके अनुसार प्रदेश में 1836 लोगों पर एक एलोपैथी डॉक्टर है, अब अगर मध्यप्रदेश को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मापदंड पूरा करना पड़े तब 90 हजार डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी। वर्तमान स्थिति में इस स्तर को पूर्ण करने के लिए 51 हजार डॉक्टर की और आवश्यकता है। देखा जाए तो मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत 65 हजार चिकित्सक है परंतु इनमें से कुछ की मृत्यु हो गई है तो कुछ प्रदेश छोड़कर चले गए है, और 49 हजार चिकित्सक ही बचे है।

समस्या की गहनता में जाएं तो प्रदेश के किसी भी जिले के शासकिय चिकित्सालय में देखे तो वहां डॉक्टर्स की कमी निसंदेह स्वतः दिख जाएगी। फिर विशेषज्ञो की कमी रोगियों के लिए भयंकर संकट के रुप में उभरता हुआ सामने है। इसका एक कारण यह भी है कि डाक्टर शासकीय अस्पताल में कार्य करना ही नहीं चाहते और छोटे शहरो में जाना नहीं चाहते हैं वे सरकारी अस्पताल से ज्यादा प्राइवेट होस्पीटल को प्राथमिकता देते हैं। सरकार का प्रोत्साहन भी इस समस्या का समाधान नहीं करता, क्योंकि डाक्टर बन जाने के बाद सरकारी सिस्टम में रोगियों को हेंडल करने की मानसिकता नहीं बन पाती और माहौल निजी की तरह मिल नहीं पाता। इसीलिए कार्य करने की प्राथमिकता सरकारी से ज्यादा प्राइवेट होस्पीटल को दी जाती है।

वर्तमान समय में चिकित्सा सेवा कार्य नहीं रह गया यह भी इस समस्या का मुख्य कारण माना जा सकता है, अब हर किसी को सेवा का मेवा ज्यादा ही चाहिए इसीलिए सरकारी चिकित्सक भी प्राइवेट अस्पताल की पेड़िया चढ़ने में कोई संकोच नहीं करता साथ ही ड्यटी टाइम के अलावा वह अपने घर पर या अन्य स्थान पर खोले गए क्लीनीक पर अपनी सेवा के उचित दाम रोगियों से लेता है। डॉक्टरी पेशा धनार्जन का अधिक हो गया है माता-पिता भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं तब यही सोच रखकर बनाते हैं कि उसकी पढ़ाई पर जो खर्च किया उसका सौ गुना उनके झोली में पुनः आ जाए। इसीलिए चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने से पहले संकल्प लेकर आने वाले डाक्टर धनार्जन के लिए पूरी निष्ठा से कार्य आरंभ कर देते हैं। इस समस्या का मूल महंगी चिकित्सा शिक्षा तो है ही साथ ही साथ सीमित सरकारी अवसर होना भी है।

मध्यप्रदेश चिकित्सा महासंघ के मुख्य संयोजक डॉक्टर राकेश मालवीय के अनुसार स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा किसी देश की बुनियाद है, जिसमें निवेश को लेकर सरकार को पीछे हटना नहीं चाहिए। शासकिय डॉक्टरो के लिए उचित अनुकूल वातावरण आकर्षक वेतन, पदोन्नति सुरक्षा, सम्मान आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा यह कि निजी अस्पताल खोलने के लिए इतने नियम, टेक्स और औपचारिकता है कि लोग निवेश करने से बचते हैं। इस तरह प्रदेश की स्थिति को भांपते हुए लगता है कि आगामी 20 वर्षों तक प्रदेश में डॉक्टर की कमी को दूर होने के आसार नहीं लग रहे हैं।

मध्य प्रदेश में नए शासकिय और निजी मेडिकल कॉलेज खुल जाने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी मगर वर्तमान स्थिति देखे तो नए चिकित्सकों को प्रदेश का वातावरण पसंद नहीं आ रहा है। इस बात की पूष्टी इस आधार पर की जा सकती है कि, मेडिकल काउंसिल में प्रतिवर्ष 700 से 800 डॉक्टर पंजीकृत एनओसी लेकर या तो दूसरे राज्य या बड़े शहर या फिर विदेश चले जाते हैं। नए स्थायी पंजीयन 1500 से 2000 के बीच होते हैं, जिसके अनुसार वास्तवीक में संख्या बढ़कर 1200 ही हो रही है। प्रदेश में महंगी चिकित्सा शिक्षा के प्रारुप में कोई परिवर्तन नहीं होने के आसार है मध्यम वर्ग के बहुत से युवा चिकित्सा क्षेत्र में सेवा देने के लिए आने को तैयार है परंतु आर्थिक स्थिति के कारण उनके लिए यह संभव नहीं हो पाता है।

रिकेश बैरागी

प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के कारण नागरिको के साथ छल, धोका, और जालसाजी हो रही है, क्योंकि प्रदेशभर में झोलाछाप डॉक्टरों ने अपना जाल बिछा रखा है। गांव-गांव झोलाछाप डॉक्टर अपनी दुकानदारी लगाकर बैठे है। स्थानीय नेता की शह में और चिकित्सा क्षेत्र के जांच अधिकारी से सांठगांठ के चलते ग्रामीणों का उपचार अंदाज के अनुसार किया जाता है इस उपचार के दौरान कभी अधिक डोज के कारण बहुत से रोगियों की मौत भी हो चुकी है, मगर फिर भी सरकार झोलाछाप डॉक्टरों के विरोध में कोई नियम कानून नहीं लेकर आती है।

बहरहाल, विशेषज्ञ नहीं तो रोगी के रोग को समझने में समस्या होती है और इसी कारण उपचार के लिए रोगी को अन्यत्र स्थानों पर भटकना पड़ता है। डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन तो दिया ही जाना चाहिए साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा के समय मानवीय संवेदना और सेवा भाव की नेतिक शिक्षा से भी चिकित्सको को अवगत कराना होगा। उन्हें बताना होगा चिकित्सक पैशा जितना धनार्जन का है उससे अधिक महत्वपूर्ण सेवा का भी है।

रोड के दायरे में आ रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए एमपीआरडीसी ने लिखा पत्र

थांदला-रतलाम मार्ग की जद में कई निर्माण, ओवर ब्रिज के चलते बामनिया को छोड़कर कार्य जारी

माही की गूंज, बामनिया/करवड़।

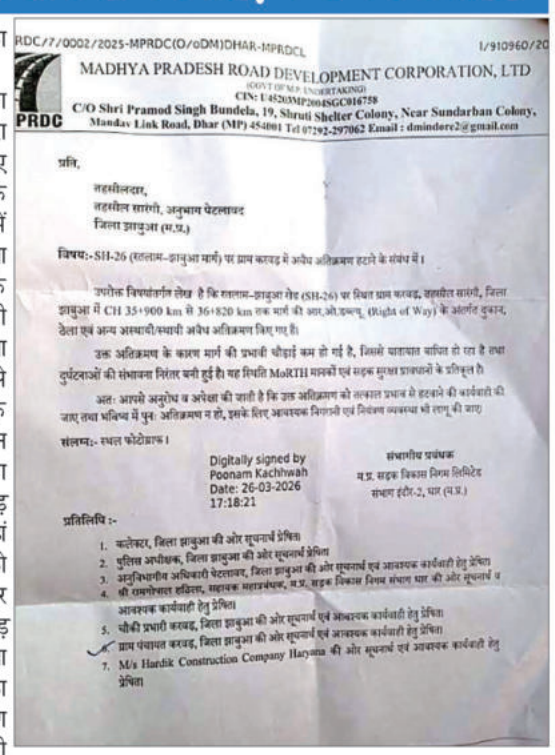

झाबुआ से होकर थांदला, खवासा, बामनिया, करवड़ होकर रतलाम स्टेट हाइवे का निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है। मार्ग निर्माण के ठेकेदार द्वारा टुकड़ों में मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पुलियों ओर ब्रिज के कार्य भी प्रगति पर हैं और ग्राम पंचायत करवड़ में कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायत करवड़ के मुख्य चौराहे पर सड़क के दोनों और बनी अतिक्रमण में अस्थाई दुकाने रोड निर्माण के जद में आने से उनको हटाने के लिए एमपीआरडीसी ने ग्राम पंचायत से मांग की। जिसके बाद कई लोगों ने अपनी अस्थाई दुकानें हटा ली या पीछे ले ली। लेकिन कई लोग अभी उसी स्थान पर जमे हुए है। जिससे मार्ग निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है।

राजस्व विभाग को अतिक्रमण हटाने के लिए भेजा पत्र

ग्राम करवड़ में सड़क की जद में आ रहे अतिक्रमण को लेकर मार्ग की निर्माण एजेंसी एमपीआरडीसी की ओर से संभागीय प्रबंधक ने अतिक्रमण हटाने के लिए स्टेट हाइवे 26 को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए राजस्व विभाग सारंगी टप्पा तहसील को पत्र लिख कर अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है।

बामनिया को छोड़ के आगे बढ़ा ठेकेदार, ओवर ब्रिज को लेकर अटका मामला

रोड निर्माण ठेकेदार द्वारा थांदला से होते हुए खवासा तक टुकड़े-टुकड़े में निर्माण किया गया जो बामनिया के पास सातेर घाटी पर आकर रुक गया और बामनिया से लाडकी नदी के बीच लगभग तीन किलोमीटर का निर्माण कार्य छोड़ कर आगे का कार्य शुरू कर दिया गया। यहां मामला रेलवे के ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर अटका हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 21 करोड़ से अधिक की राशि का आवंटन किया गया। लेकिन अब तक ब्रिज निर्माण का रास्ता साफ नहीं हुआ है न ही ब्रिज निर्माण विभाग की ओर से इसका कोई टेंडर जारी किया गया। ब्रिज निर्माण किस क्षेत्र से निकलेगा फिलहाल ये भी पूरी तरह से तय नहीं है। वहीं बिना ब्रिज के यदि रोड का निर्माण किया गया तो बामनिया के मुख्य चौराहे से लेकर रतलाम रोड पर अतिक्रमण की जद में बड़े-बड़े निजी ओर सरकारी निर्माण आ रहे है। फिलहाल तीन किलोमीटर के मार्ग निर्माण को होल्ड किया गया है।

RDC/7/0002/2025-MPRDC(O/oDM)DHAR-MPRDCL 1/910960/20
MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION, LTD
(GOVT OF M.P. UNDERTAKING)
CIN: U45203MP2004SGC016758
C/O Shri Pramod Singh Bundela, 19, Shruti Shelter Colony, Near Sundarban Colony, Mandav Link Road, Dhar (MP) 454001 Tel 07292-297062 Email : dmindore2@gmail.com

प्रति,
तहसीलदार,
तहसील सारंगी, अनुभाग पेटलावद
जिला झाबुआ (म.प्र.)

विषय:- SH-26 (रतलाम-झाबुआ मार्ग) पर ग्राम करवड़ में अवैध अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि रतलाम-झाबुआ रोड (SH-26) पर स्थित ग्राम करवड़, तहसील सारंगी, जिला झाबुआ में CH 35+900 km से 36+820 km तक मार्ग की आर.ओ.डब्ल्यू. (Right of Way) के अंतर्गत दुकान, ठेला एवं अन्य अस्थायी/स्थायी अवैध अतिक्रमण किए गए है।

उक्त अतिक्रमण के कारण मार्ग की प्रभावी चौड़ाई कम हो गई है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है तथा दुर्घटनाओं की संभावना निरंतर बनी हुई है। यह स्थिति MoRTH मानकों एवं सड़क सुरक्षा प्रावधानों के प्रतिकूल है।

अतः आपसे अनुरोध व अपेक्षा की जाती है कि उक्त अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्यवाही की जाए तथा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न हो, इसके लिए आवश्यक निगरानी एवं नियंत्रण व्यवस्था भी लागू की जाए।

संलग्न:- स्थल फोटोग्राफ।

Digitally signed by Poonam Kachhwah Date: 26-03-2026 17:18:21

संभागीय प्रबंधक
म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड
संभाग इंदौर-2, धार (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-
1. कलेक्टर, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री रामगोपाल हवित्त, सहायक महाप्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम संभाग धार की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. चौकी प्रभारी करवड़, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. ग्राम पंचायत करवड़, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. M/s Hardik Construction Company Haryana की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

टीटीई की परीक्षा के विरोध में लामबद्ध हो रहे शिक्षक संगठन

परीक्षा को लेकर शिक्षकों की अलग-अलग राय

माही की गूंज, पेटलावद।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में आई मोहन सरकार के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा अनिवार्यता के निर्देश जारी किए। सरकारी आदेश के बाद शिक्षकों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। परीक्षा के पीछे कई नियमों को लेकर शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षक संगठन अब अपने स्तर पर इस परीक्षा को लेकर विरोध दर्ज करवा रहे है। शिक्षक संगठनो ने संकुल स्तर पर ज्ञापन दिया साथ ही जिला ओर ब्लाक स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ ओपीएस बहाली हेतु बुधवार को झाबुआ में विशाल रैली के साथ ज्ञापन दिया गया। मंगलवार को झकनावदा ओर पेटलावद रेस्ट हाउस में संघ की बैठक रखी गई। जिसमें 11 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पर और 18 अप्रैल को भोपाल एकत्रित होकर ज्ञापन देने के आयोजन पर चर्चा की गई। जिसमें संयुक्त मोर्चा से पप्पू हटीला, कैलाश वसुनिया, संजय मखोड़, धनराज भूरिया ने शिक्षक साथियों को संबोधित किया और कल झाबुआ में 100 प्रतिशत उपस्थित रहने हेतु प्रेरित किया। झकनावदा व बोलासा संकुल परिवार के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया।

नाले की सफाई को लेकर वार्ड वासियों को करना पड़ता है एक साल तक का इंतजार

माही की गूंज, पेटलावद।

नगर परिषद द्वारा स्वच्छता का नगर में ध्यान तो दीया जा रहा है लेकिन नगर के वार्डो के हिस्से उपेक्षा का शिकार होने से स्वच्छता अभियान की पोल खुलती जा रही है। नगर के वार्ड नंबर एक राम शरणम् के पीछे वाले नाले की सफाई नहीं होने से वार्ड वासियों को परेशान होना पड़ रहा है। इस नाले में साल में एक बार ही जेसीबी के माध्यम से सफाई कर गंदा पानी कूड़ा कचरा निकाला जाता है। क्योंकि इस नाले में बारिश का पानी बहता है और गर्मी के दिनों मे धीरे-धीरे नाले में जो भी कचरा बारिश के समय आता है वही कचरा गर्मी के दिनों में नाले को जाम कर देता है। ऐसे में वार्ड वासियों को गंदगी की बदबू मच्छरों का प्रकोप से खतरा बना रहता है जिससे बीमारियां फैलती है। इस समस्या को लेकर वार्ड नंबर 1 के नाले की हर बार मौखिक सूचना वार्ड वासियों के द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष, सीएमओ को देना पड़ती है फिर भी समय रहते सफाई नहीं होती है। क्या इस वार्ड में जानता निवास नही करती हैं? नगर के वार्ड नंबर 1 दामोदर कॉलोनी में कई लोग निवास करते हैं। नाले के पास ही राम शरणम् है। यहा नगर के कई भक्त महिलाएं, पुरुष, बच्चे भजन करने के लिए सुबह-शाम आते हैं, जिससे कई लोगों को इसी गंदे नाले की बदबू से परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

डे-नाइट करवड़ प्रीमियम लीग का समापन, आदि ब्लास्टर ने जीता खिताब

माही की गूंज, करवड़। करवड़ में आजाद क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आठ दिवसीय 29 वे डे-नाइट क्रिकेट मैच का महाकुंभ संपन्न हुआ। आजाद क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में आयोजित 29वें डे-नाइट करवड़ प्रीमियम लीग का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। 28 मार्च से शुरू हुए इस क्रिकेट महाकुंभ में ग्रामीण की प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच मिला जहां क्षेत्र की दिग्गज टीम ने विधायक ट्रॉफी के लिए अपना दमखम दिखाया। उद्घाटन समारोह के दौरान खेल के प्रति युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। यह टूर्नामेंट आगामी 28 मार्च से प्रारंभ होकर 5 अप्रैल तक हुआ जो दूधिया रोशनी में खेला गया। जिसमें कुल 8 प्रमुख टीमें रही।

क्रिकेट मैच के दौरान ग्रामीणों ने पुरस्कारों की घोषणा की जिससे खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना कर दिया। इसमें प्रथम स्थान पर आदि ब्लास्टर रायपुरिया, द्वितीय स्थान पर करवड़ सुपर किंग एवं तृतीय स्थान पर थाला एक्सप्रेस घुघरी रहा। प्रथम व तृतीय इनाम कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया मध्य प्रदेश शासन मंत्री के द्वारा 55,555 रुपए दिए गए एव तृतीय ईनाम के साथ-साथ आकर्षक ट्रॉफियां भी महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के सौजन्य से प्रदान की। वहीं द्वितीय पुरस्कार की राशि सरपंच विकास गामड़ की ओर से दी। मैन ऑफ द सीरीज का सम्मान अखंड प्रताप सिंह राणावत की ओर से दिया गया। आयोजन को सफल बनाने के लिए कप्तान रितेश गामड़, अर्पित पाटीदार और दीपक पाटीदार की टीम पूरी मुस्तैदी से जुटी थी। करवड़ के खेल मैदान में दर्शकआधी रात तक डटे रहे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शालिग्राम पटेल, सरपंच विकास बाबूलाल गामड़, उप सरपंच राजेश पाटीदार, शैलेंद्र सिंह राठौड़ गंगाखेडी, राजू गेहलोत, नगिन भंडारी, बद्रीलाल भालोड, भगवान सिंह गामड़ आदि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

सरकारी गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ने से उलझन में किसान

पूर्व जनपद उपाध्यक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल

माही की गूंज, सारंगी।
संजय उपाध्याय

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की तारीख बढ़ाए जाने से किसानों में खासा आक्रोश है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 अप्रैल के स्थान पर 10 अप्रैल से खरीदी का निर्णय लिया गया है। खरीदी लेट होने से किसानों में नाराजगी है लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और बारिश की वजह से फसल खराब होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में उपज को सुरक्षित रखना भी किसानों के लिए चुनौती बन रहा है। इस मामले में किसान हीरालाल पाटीदार , रवि पटेल, राजू भूरिया, कालू खराड़ी, गिरधारी लाल पाटीदार, संदीप पाटीदार ने बताया कि, एक अप्रैल से खरीददारी शुरू होना थी किसानो को पैसे की भी जरूरत है बाजार में भाव भी कम मिल रहे हैं। किसानों को आ रही परेशानी को लेकर योगेंद्र सिंह राठौर ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि, वर्तमान में किसान अपनी फसल को कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर है और इधर-उधर भटक रहे हे। सरकार खरीदी नहीं कर रही है और बहाने बना रही है। ऐसे में यह किसानों के साथ एक तरफ से गलत हो रहा है। क्योंकि समय पर खरीदी नहीं होने से किसान परेशान है। जब गेहूं खरीदी की तारीख बडाई तो बैंकों में लोन जमा करने की तारीख क्यों नहीं बडाई। किसानों के पास बैंकों में लोन जमा कराने के लिए पैसा नहीं है। गेहूं खरीदी नहीं हुई है ऐसे में किसान करें तो क्या करे? किसानों ने सरकार से मांग की है कि, बैंक कर्ज जमा करने के लिए सरकार को विचार कर तारीख बढ़ाना चाहिए।

बे मौसम बारिश ने बढ़ाई चिंता

बे मौसम बारिश के कारण किसानो की चिंता बढ़ गई है उन्हें फसल के नुकसान का डर बना हुआ है। मंगलवार शाम को क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई जिससे गेहूं की फसल के नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है। कई किसानों की फसल काटने के बाद उपज खलिहान में ही पड़ी है।

नेत्रदानः दो नेत्रहीनों के जीवन में जलेगा आशा का दीप

माही की गूंज, पेटलावद।

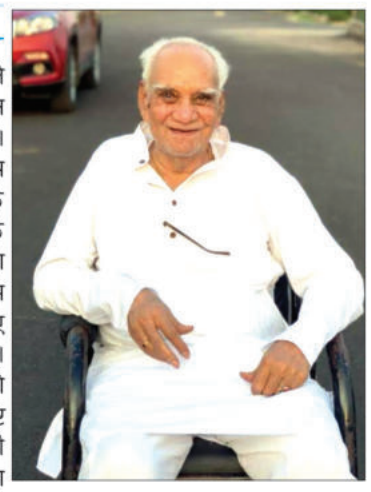

कहते हैं कि, जीवन भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन अच्छे कर्म अमर हो जाते हैं। पेटलावद निवासी स्वर्गीय अनोखी लाल मोदी के देहावसान के पश्चात उनके परिवारजनों ने संवेदनशीलता और मानवता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नेत्रदान का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय से दो नेत्रहीन व्यक्तियों को नई दृष्टि और नया जीवन मिलने की राह प्रशस्त हुई है। रितेश नीमजा ने तेरापंथ युवक परिषद को नेत्रदान की सूचना दी गई। तथा पुत्र प्रबोध, प्रवीर एवं अनिल मोदी की सहमति से यह पुनीत कार्य सम्पन्न हुआ। तेयूप पेटलावद के समन्वय से रतलाम स्थित डा. लक्ष्मीनारायण पांडे मेडिकल कॉलेज आई बैंक की टीम पहुँची और विधिवत नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की।

परिषद अध्यक्ष अभिषेक पटवा ने बताया कि, इस कार्य में मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. अनिता मुथा को सूचित किया गया। जिनके निर्देश पर नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. रिशेन्द्र सिसोदिया के नेतृत्व में नर्सिंग ऑफिसर विनोद कुशवाह, डॉ सौरभ पांडे, सहायक जीवन देवड़ा आदि आई बैंक टीम द्वारा मृतात्मा का कार्निया लिया एवं उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तेयुप पेटलावद अध्यक्ष ने बताया कि, नेत्रदान नेक कार्य है यह किसी के अंधकारमय जीवन में प्रकाश भरने का माध्यम है। यदि प्रत्येक परिवार इस दिशा में जागरूकता दिखाए, तो समाज से अंधत्व की पीड़ा को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

निर्माण एजेंसी गायब, नवीन ग्रिड का कार्य अधूरा

माही की गूंज, खवासा।
सुनिल सोंलकी

ग्रामीण अंचलों में 24 घंटे विद्युत लाइट मिले इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने आरडीएसएस के तहत कार्य शुरू किया गया। जिसमें ठेट ग्रामीण अंचलों में जहां मकान बने हुए हैं, वहां तक विद्युत लाइन के तार के साथ केबल बिछाने का कार्य इन दिनों बड़ी ही तीव्र गति से किया जा रहा है। वही कई जगह कार्य में काफी लापरवाही व अनियमिता भी बरती जा रही है। लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारी इस और कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण कार्य करने वाली निर्माण एजेंसी मनमानी व अनियमिता के साथ कार्य कर रही है। बताते हैं कि, खवासा विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले सेमलिया ग्रिड़ पर नवीन कार्य शुरू किया गया जिसमें पूरा नए सिरे से लाइन बिछाने के साथ वहां एक बड़ी ग्रिड़ का निर्माण किया गया है। जिससे तलावड़ा, कुकड़ीपाड़ा, बड़ी संगत, आदि क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुगम तरीके से पहुंचाने का उद्देश्य सरकार का है। लेकिन ग्रिड़ पर कार्य करने वाली निर्माण एजेंसी निम्न व घटिया तरीके का कार्य करके अपनी इति श्री कर रही है।

कुछ ऐसा ही इन दिनों सेमलिया ग्रिड के नाम से तलावड़ा ग्रिड़ का काम चल रहा था, यहां ग्रिड़ बनाने के साथ एक बड़ा भवन का निर्माण भी किया गया था। जानकारी के अनुसार कार्य नई दिल्ली नोएडा की स्पान कंपनी को मिला था। सिविल इंजीनियर के रूप में राम जी साहू की देख रेख मे कार्य चल रहा था। लेकिन कार्य निम्न व घटिया तरीके से करने के बाद सिविल इंजीनियर तक गायब है बताया जा रहा हैं। यहां भवन का भी निर्माण किया गया जिसमें विद्युत लाइन के साथ ही लेथ-बाथ के साथ कर्मचारी को रूकने हेतु सभी सुविधा भी देना थी। लेकिन वहां अभी सभी सुविधा अधूरी पड़ी हुई है। या कहे की कार्य अधूरा बताते हैं। भवन का कार्य पेटी ठेकेदार के रूप में रम्भापुर के प्रकाश नायक ने लिया था, उनके द्वारा भवन का निर्माण किया गया था लेकिन उन्होंने भी निम्न घटिया तरीके का कार्य किया व आज भी उस भवन का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।

यहां पर पदस्थ लाइनमैन रतन चंद्रावत से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, ग्रिड़ तो सुचारू रूप से सभी जगह शुरू कर दी गई है, लेकिन यहां जो भवन बनाया गया इसमें लेथ-बाथ अभी अधूरे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि, ग्रिड़ हैंडओवर हुआ है, या नहीं वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में बता सकते हैं। फिलहाल तो यहां अधूरा कार्य ही हुआ है लेकिन कोई भी इस और ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया उसके बाद भी इस समस्या का निदान नहीं हो रहा है। यहां रहने वाले स्टाफ को लेथ-बाथ की समस्या बनी हुई है, और भवन में काफी अभी भी निर्माण कार्य बाकी है। जिसे जल्द से जल्द कार्य होना चाहिए यही मांग की जा रही है।

वही भवन का कार्य करने वाले ठेकेदार प्रकाश नायक से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मैं, लड़कों से पूछ कर बताता हूं कि वहां कितना अधूरा कार्य है, क्योंकि मैं भी साइट पर नहीं गया इसलिए क्या स्थिति पुछने के बाद ही बता पाऊंगा।

संपादकीय

मंडी पोर्टलों की बाधा

कहने को तो देश डिजिटल क्रांति के दौर में पहुंच चुका है और वित्तीय लेनदेन से लेकर तमाम क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक वरदान साबित हो सकती है। लेकिन हमें यह मानकर चलना चाहिए कि देश का परंपरागत किसान डिजिटल सुविधाओं के उपयोग में खुद को सहज महसूस नहीं करता। आधुनिक डिजिटल तकनीक का प्रयोग नई पीढ़ी की सोच के अनुरूप है, लेकिन पुरानी पीढ़ी इसके उपयोग में खुद को असहज पाती है। कमोबेश किसानों के कल्याण के लिए बनाये गए मंडी पोर्टलों पर भी यही बात लागू होती है। जाहिरा तौर पर किसानों के लिये मंडी पोर्टलों का उपयोग आसान होना चाहिए। बाकायदा किसानों को डिजिटल साक्षर बनाने की मुहिम चलाने की जरूरत भी है। सही मायनों में डिजिटलीकरण का मुख्य उद्देश्य कृषि उपजों की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाना था। लेकिन हरियाणा में जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है। दरअसल, हम एक आम किसान से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह शहरी लोगों की तरह पोर्टलों, पासवर्डों और प्रक्रियात्मक पेचीदगियों के जाल का सहजता से उपयोग कर सके। यही वजह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का लाभ उठाने के लिये उसे एक जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि राज्य भर की मंडियों से द ट्रिब्यून में प्रकाशित हालिया रिपोर्टों से एक जैसा पैटर्न नजर आया है। अब राज्य में फसलों की बिक्री के लिये अनिवार्य पोर्टल-ई-खरीद और मेरी फसल,मेरा ब्योरा यानी एमएफएमबी- साइट क्रैश, डेटा विसंगतियों और सत्यापन की विफलताओं से ग्रस्त है। जिससे कई तरह की समस्याओं से किसानों को रूबरू होना पड़ रहा है। यहां तक कि कई जिलों में, किसानों को गेट पास तक नहीं दिए गए हैं। वजह यह बतायी जा रही है कि किसानों का रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहा है। कई बार अंतिम व महत्वपूर्ण क्षणों में सर्वर ने काम नहीं किया। जिसका खमियाजा फसल बेचने आने वाले किसानों को उठाना पड़ रहा है।

दरअसल, ऐसी अनेक तकनीकी जटिलताओं के परिणाम तात्कालिक व गंभीर बताये जाते हैं। किसानों की फसल तो बिक्री के लिये तैयार है, लेकिन कतिपय कारणों से उसे मंडियों में प्रवेश करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है किसान अपने खून-पसीने की फसल निजी व्यापारियों को बेचने को विवश हो जाते हैं। किसान की मजबूरी ये होती है कि वह जल्द से जल्द फसल बेचना चाहता है। उसे अपने पहले के खर्च निकालने हैं और अगली फसल की तैयारी करनी है। जिसके चलते वह तुरंत भुगतान की आस में कम दाम में भी व्यापारियों को फसल बेचने को बाध्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी एजेंसियां खरीद नहीं कर रही हैं, लेकिन फसल की आवक का एक छोटा हिस्सा ही खरीद पायी हैं। जो फसल खरीद के वायदे और वास्तविक तैयारी के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। कुछ आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। विशेष रूप से, हरियाणा में गेहूं की खरीद को 80 लाख टन से घटाकर 72 लाख टन करने से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप में नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते उन्हें आर्थिक घाटा उठाना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि जो अनाज एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता है, उसे किसान व्यापारियों को एमएसपी से 400 से पांच सौ रुपये कम दाम पर बेचने को मजबूर है। यानी एमएसपी के मूल उद्देश्य के विपरीत यह किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि डिजिटलीकरण का लक्ष्य व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। लेकिन इस प्रणाली की उपयोगिता तभी है जब सर्वर ठीक से काम कर रहा हो। साथ ही लोग इसका उपयोग बेहतर ढंग से करना जानते हों। यह प्रक्रिया छोटे और गरीब व निरक्षर किसानों को प्रोसेस से बाहर कर देती है। जिनकी सेवा का दावा व्यवस्था अक्सर करती है। एक विसंगति यह भी कि इसमें कोई बैकअप सिस्टम नहीं है। पोर्टल के फेल होने पर खरीद रुक जाती है। यदि एमएसपी का लाभ कमजोर डिजिटल प्रणाली की वजह से किसान को नहीं मिलता, तो यह किसानों का सुरक्षा कवच नहीं रह जाता है।

शर्तों के साथ ईरान और अमेरिका के बीच 15 दिन का सीज फायर

सनत जैन

ईरान और अमेरिका के बीच दो सप्ताह के लिए युद्ध विराम के लिए सहमति बन गई है। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया। ईरान ने भी अधिकृत रूप से इसकी घोषणा की। सीज फायर के बाद हमले तत्काल रूप से बंद हो गए हैं। ईरान ने इसके लिए अधिकृत रूप से आदेश जारी किए हैं। युद्ध विराम को लेकर 10 शर्तों के साथ ईरान ने प्रस्ताव पेश किया है। चीन द्वारा दोनों पक्षों को समझाइस दिए जाने के बाद 15 दिन के लिए युद्ध विराम घोषित किया गया है। इसकी घोषणा होते ही, इसके सकारात्मक परिणाम भारत सहित दुनिया के सभी देशों में देखने को मिले हैं। एक नई आशा की किरण जागी है। दोनों पक्ष गंभीरता के साथ विचार करके स्थाई रूप से युद्ध रोकने और शां?ति के लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए दोनों पक्षों का एक मंच पर आना जरूरी था। पाकिस्तान ने तीनों पक्षों के बीच बातचीत के ?लिये जो प्रयास किया, वह सार्थक हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस फैसले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर का उल्लेख किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह उल्लेख किया है, ईरान को स्टेट आफ हार्मोज को फिर से खोलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, अमेरिका ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अमेरिका अब तेहरान के साथ निर्णायक फैसले की स्थिति में आ गया है। अब जो भी समझौता होगा वह दीर्घकालिक शांति के लिए होगा। ईरान की ओर से शीर्ष अधिकारी बातचीत करने के लिए पा??किस्तान आएंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस बातचीत में शामिल होंगे। इस फैसले के आते ही सारी दुनिया के देशों ने राहत की सांस ली है। ऊर्जा संबंधी संकटों और युद्ध को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी। उससे सारी दुनिया को अस्थाई रूप से राहत मिली है। भारत में इसका बड़ा असर देखने को मिला। शेयर बाजार ने 2800 अंकों की छलांग लगाई। कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी के साथ गिरे। इस युद्ध में अमेरिका द्वारा ईरान को खत्म करने की जो धमकी दी जा रही थी, चीन, रूस और उत्तर कोरिया के इस युद्ध में शा?मिल होने की संभावना बन गई थी। पिछले एक साल से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ को लेकर दबाव बना रहे थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाकर अमेरिका में बंधक बनाया गया। इसके तुरंत बाद ईरान पर हमला किया गया। इससे सारी दुनिया के देश अमेरिका से नाराज थे। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी लिए बिना जिस तरह से ईरान पर हमला किया था। अमेरिकी कानून के अनुसार केवल 45 दिन तक वह इस तरह की कार्रवाई राष्ट्रप?ति कर सकते थे। इसके पहले उन्हें संसद की अनुमति लेना अनिवार्य था। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। एक महीने से अधिक युद्ध चलते हुए हो गए थे। युद्ध में ईरान के साथ-साथ इजराइल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिन खाडी के देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, ईरान ने लगभग सभी में ध्वस्त कर ?दिये हैं। अमेरिका की जो साख दु?निया में बनी हुई थी, इस युद्ध में वह लगभग खत्म हो गई है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध से बाहर निकलना चाहते थे। इसमें पाकिस्तान ने पहल की। चीन ने अपनी सामरिक और आर्थिक शक्ति का एहसास कराकर अमेरिका और ईरान दोनों को एक मंच पर लाने का जो काम किया है। युद्ध ??विराम से सारे विश्व को राहत मिली है। अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में सबसे ज्यादा भूमिका इजरायल की थी। ग्रेटर इजरायल की परिकल्पना पर काम कर रहे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मोसाद द्वारा जो अमेरिका को जो जानकारी दी गई थी, वह सही नहीं थी। अति उत्साह में डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूद गए। जिसके कारण अब उन्हें राष्ट्रपति पद को बचा पाना मुश्किल दिख रहा है। इसके अलावा अमेरिका में नवंबर माह में जो चुनाव होने हैं। उसको लेकर उन्हें अपनी पार्टी से चुनौती मिलने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप का स्वभाव है वह आक्रामक होकर अपनी विपक्षी के ऊपर हमला करते हैं। पिछले 1 साल में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक्सपोज हुए हैं। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की जो छवि होती थी, उसमें बहुत बड़ा बट्टा लग गया है। अमेरिका को सारी दुनिया के देशों से कई तरह की चुनौतियां मिलना शुरू हो गई हैं। डॉलर मुद्रा को चुनौती मिल रही है। नाटो और यूरोपीय देशों ने अमेरिका का साथ एक तरह से छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में ईरान से ज्यादा अमेरिका को युद्ध ?विराम की जरूरत थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसमें सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे। जिस तरह से ईरान ने तेल अवीव और इजरायल के विभिन्न हिस्सों में हमला करके जो नुकसान पहुंचाया है, उसके कारण अब इजराइल भी ठंडा पड़ गया है। इजराइल का इतिहास रहा है कि वह अपनी बात पर ज्यादा देर कायम नहीं रहता है। इस युद्ध विराम में यदि कोई पलीता लगाने का काम करेगा, तो वह इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ही होंगे। इन 15 दिनों में कोई हमला नहीं हुआ तो निर्णायक समझौते के लिए वातावरण बनने में अब कोई दिक्कत नहीं है। ईरान ने अपनी ताकत का एहसास कर दिया है। पिछले 47 सालों से उसके ऊपर लगातार प्रतिबंध थोपे जा रहे थे। इस युद्ध के बाद अब उसके साथ बातचीत में समान रूप से व्यवहार करना होगा। इस युद्ध ने सभी के अहंकार को तोड़ दिया है। सभी पक्षों को युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। सारी दुनिया के देशों को इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। कच्चा तेल, गैस, खाद्यान्न एवं अन्य सामान की आपूर्ति दु?निया भर में बाधित हुई है। सारी दुनिया के देश चाहते थे, जल्द से जल्द इस मामले का कोई हल निकले। जो हुआ है, वह बहुत अच्छा हुआ है। ईरान इस बार पूरी तरह सतर्क है। उसके पास जो अस्त्र-शस्त्र हैं। जितना अच्छा उपयोग इस युद्ध में ईरान ने किया है, उसके बाद लगता नहीं है, अमेरिका और इजरायल ईरान के साथ कोई खेल करेंगे। कच्चे तेल के दाम घटने के साथ गैस की निर्बाध आपूर्ति शुरू होगी। कुल मिलाकर इस युद्ध विराम का स्वागत सभी देशों द्वारा किया जा रहा है। रूस-चीन जैसी महाशक्तियां भी युद्ध खत्म कराने मे अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास कर रहे थे। बातचीत में स्थाई समाधान खोज लिया जाता है। तो यह दुनिया के लिए शांतिपूर्ण प्रयासों की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

जनादेश २०२६ – विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा और सत्ता के नए समीकरण

योगेश कुमार गोयल

पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों ने देश की राजनीति को उबाल पर ला दिया है। केरल से लेकर असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी तक सियासी हलचल अपने चरम पर है। रैलियों की गूंज, वादों की बरसात और आरोप-प्रत्यारोप के तीखे तीरों के बीच लोकतंत्र का यह उत्सव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। हर राजनीतिक दल अपने-अपने एजेंडे, घोषणापत्र और रणनीति के साथ मैदान में है और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। इस बार का चुनाव केवल सरकार बनाने का साधन नहीं बल्कि बीते पांच वर्षों के कामकाज का जनमत संग्रह और आने वाले राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णायक क्षण है।

इन पांच राज्यों की कुल 824 विधानसभा सीटों पर लगभग 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि 116 लोकसभा सीटों के प्रभाव क्षेत्र से जुड़ा हुआ वह राजनीतिक रणक्षेत्र है, जो राष्ट्रीय राजनीति की धुरी को प्रभावित कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम भी बेहद दिलचस्प है, असम, केरल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में दो चरणों (23 और 29 अप्रैल) में वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 मई को घोषित होंगे और उसी दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किसके पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया। इस बार का चुनावी परिदृश्य कई स्तरों पर जटिल और बहुआयामी है। सत्ताधारी दल जहां अपने विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और 'डबल इंजन' जैसे नारों के सहारे जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असमानता और प्रशासनिक खामियों को मुद्दा बनाकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। यह संघर्ष अब केवल सत्ता का नहीं रहा बल्कि विचारधारा, नीतियों और विकास के मॉडलों की प्रतिस्पर्धा में बदल चुका है।

सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है पश्चिम बंगाल, जहां राजनीतिक तापमान सबसे ज्यादा है। 294 सीटों वाली विधानसभा में 6.44 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता पर कब्जा बनाए रखा था जबकि भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार मुकाबला और अधिक तीखा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस अपने 'बंगाल मॉडल', महिला सशक्तिकरण योजनाओं और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों के साथ मैदान में है, वहीं भाजपा 'डबल इंजन' सरकार के वादे और घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखता दे रही है। रोजगार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे भी चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यहां मुकाबला बेहद कांटे का होगा, एक तरफ ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत दांव पर है तो दूसरी ओर भाजपा के लिए यह पूर्वी भारत में विस्तार का सुनहरा अवसर है।

असम का चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं है। 126 सीटों वाली विधानसभा में 2.25 करोड़ मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यहां मुख्य सवाल यही है कि क्या भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर पाएगी या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वापसी का रास्ता तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा विकास, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर जनता के बीच है। वहीं विपक्ष सीएए-एनआरसी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सक्रियता ने इस चुनाव को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। असम में परिणाम न केवल राज्य की राजनीति बल्कि पूर्वोत्तर भारत में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेंगे।

दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल की राजनीति अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का प्रभाव इतना गहरा है कि राष्ट्रीय दलों की भूमिका सीमित हो जाती है। 234 सीटों वाली विधानसभा में 5.67 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। पिछले चुनाव में डीएमके गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी और इस बार भी वह अपने 'द्रविड़ मॉडल', सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर मैदान में है। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन महंगाई, बिजली संकट और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। इसके अलावा अभिनेता विजय की पार्टी का चुनावी मैदान में उतरना एक नया समीकरण बना सकता है, खासकर युवा मतदाताओं के बीच।

केरल में 140 सीटों के लिए 2.7 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। यहां का चुनाव पारंपरिक रूप से सत्ता परिवर्तन के लिए जाना जाता रहा है लेकिन पिछले चुनाव में वाम मोर्चे ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था। इस बार यदि वह तीसरी बार सत्ता में आता है तो यह एक नया राजनीतिक अध्याय होगा। वाम मोर्चा अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के मॉडल को प्रमुखता दे रहा है जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हमलावर है। भाजपा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है।

पुदुचेरी भले ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन यहां की राजनीति बेहद संवेदनशील और निर्णायक है। 30 सीटों वाली विधानसभा में 9.44 लाख मतदाता मतदान करेंगे। यहां गठबंधन राजनीति का महत्व सबसे अधिक है, जहां छोटे-छोटे वोट अंतर भी सत्ता की दिशा तय कर सकते हैं। पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी और इस बार भी वह अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल सत्ता वापसी के लिए संघर्षरत हैं। इन सभी राज्यों में एक समान बात यह है कि वोट प्रतिशत और सीटों का समीकरण हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार मामूली वोट अंतर भी भारी सीट अंतर में बदल जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल बूथ स्तर तक अपनी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार ने चुनावी अभियान को एक नई दिशा दी है, जहां नैरेटिव की लड़ाई केवल मैदान में नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लड़ी जा रही है।

चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस बार कोई एक मुद्दा हावी नहीं है। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि संकट और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रूप में सामने आ रहे हैं। यही विविधता इन चुनावों को और अधिक जटिल और रोचक बनाती है। राजनीतिक दृष्टि से इन चुनावों को 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इन राज्यों से आने वाली 116 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यदि भाजपा असम में अपनी पकड़ बनाए रखती है, पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करती है और दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करती है, तो उसकी राष्ट्रीय स्थिति और सुदृढ़ हो सकती है। वहीं, यदि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अपनी सत्ता बरकरार रखती है तो ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति की प्रमुख धुरी बनी रह सकती हैं। केरल में वाम मोर्चे की जीत वामपंथी राजनीति के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगी जबकि तमिलनाडु में डीएमके की निरंतरता द्रविड़ राजनीति की दिशा तय करेगी।

कुल मिलाकर, यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। मतदाता इस बार खामोश जरूर हैं लेकिन उनकी चुप्पी के भीतर गहराई से सोच-विचार और निर्णय की प्रक्रिया चल रही है। 4 मई को जब परिणाम सामने आएंगे, तभी यह स्पष्ट होगा कि किसने जनता की अपेक्षाओं को समझा और किसे आत्ममंथन की आवश्यकता है। लोकतंत्र का यह महापर्व एक बार फिर यह सिद्ध करने जा रहा है कि अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है और वही निर्णय देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है।

मंडी व्यवस्था पटरी से उतरी, किसानों का सब्र टूटा, आंदोलन की आहट तेज

माही की गूंज, शुजालपुर।

शुजालपुर कृषि उपज मंडी में इन दिनों व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। किसानों को राहत देने के उद्देश्य से बनाए गए टीन शेड अब व्यापारियों के कब्जे में स्थायी भंडारण स्थल बन गए हैं। परिणामस्वरूप अन्नदाता अपनी ही मंडी में असहाय नजर आ रहा है और उसकी उपज तेज धूप व मौसम की मार झेलने को मजबूर है।

मंडी परिसर क्रमांक एक में सुबह से शाम तक किसानों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, लेकिन उन्हें न तो छाया मिलती है और न ही बैठने की समुचित व्यवस्था। खुले आसमान के नीचे बोरी-बोरी अनाज रखकर किसान अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जबकि शेड के भीतर व्यापारियों का माल व्यवस्थित रूप से रखा दिखाई देता है। यह दृश्य अव्यवस्था के साथ-साथ प्राथमिकताओं के उलट जाने की स्थिति को स्पष्ट करता है।

किसानों का आरोप है कि यह सब बिना उच्च स्तर की सहमति के संभव नहीं है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से यह आशंका और गहरी हो गई है कि जिम्मेदार या तो अनजान बने हुए हैं या जानबूझकर चुप्पी साधे हुए हैं। मंडी में चर्चा है कि ÷नियम केवल कागजों तक सीमित हैं, जमीन पर उनका पालन नहीं हो रहा।÷

इस अव्यवस्था का सीधा असर किसानों की आय पर पड़ रहा है। तेज धूप, बारिश और धूलभरी आंधियों के कारण उपज खराब होने का खतरा बना रहता है। कई किसानों का कहना है कि देरी और अव्यवस्था के चलते उन्हें अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता है, जिससे उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि नियमों के अनुसार शेड किसानों के लिए आरक्षित हैं, तो उनका उपयोग व्यापारी कैसे कर रहे हैं? क्या निरीक्षण नहीं हो रहा या जानबूझकर अनदेखी की जा रही है? यह चुप्पी अब संदेह को जन्म दे रही है।

मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वे खुलकर विरोध की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि शीघ्र ही शेड खाली नहीं कराए गए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेंगे।

अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाता है या यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल मंडी में एक ही सवाल गूंज रहा हैकृक्या अन्नदाता को उसकी ही मंडी में उसका अधिकार मिलेगा?

अंकित मूल्य सिर्फ दिखावा, जेब से वसूली असली

खेल, ग्राहक बेबस, व्यवस्था मौन या शामिल?

माही की गूंज, शुजालपुर।
अजय राज केवट

शाजापुर जिले के शुजालपुर में मदिरा बिक्री अब खुलेआम ÷दोगुनी दर÷ के खेल पर चल रही है। बोतलों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, जबकि वास्तविक कीमत काउंटर पर तय की जा रही है। स्थिति यह है कि ÷जो लिखा है, वह नहीं मिलताकृजो बताया जाता है, वही देना पड़ता है।÷

शाम होते ही मदिरा दुकानों पर एक अलग व्यवस्था लागू हो जाती है। ग्राहक बोतल उठाकर अंकित मूल्य देखता है, लेकिन भुगतान के समय उससे 20, 30, यहां तक कि 50 रुपये अधिक वसूले जाते हैं। विरोध करने पर सीधा जवाब मिलता हैकृ÷लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो।÷

यह समस्या केवल एक-दो दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक समान प्रवृत्ति बन चुकी है। इससे स्पष्ट है कि यह कोई आकस्मिक त्रुटि नहीं, बल्कि सुनियोजित दर-तंत्र है, जो बिना किसी भय के संचालित हो रहा है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आबकारी विभाग इस स्थिति पर क्या कार्रवाई कर रहा है? क्या यह सब उसकी नजर से ओझल है या जानबूझकर अनदेखी की जा रही है? स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, जिससे दुकानदारों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार यह उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और विधिक रूप से दंडनीय भी है। किंतु वास्तविकता यह है कि नियम केवल कागजों तक सीमित हैं और खुले आम वसूली जारी है।

इस पूरे प्रकरण में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित हो रहा हैकृन उसे सही मूल्य मिल रहा है और न ही शिकायत करने पर न्याय। ऐसे में लोगों के बीच यह धारणा बनती जा रही है कि ÷सब कुछ पूर्व निर्धारित है÷, जो स्थिति को और चिंताजनक बनाती है।

अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस अवैध वसूली पर रोक लगाता है या फिर नियम केवल दस्तावेजों तक सीमित रहेंगे और जमीनी स्तर पर यही स्थिति बनी रहेगी। जब व्यवस्था मौन हो जाती है, तब अनियमितताएं स्वयं मुखर हो जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध वसूली का सिलसिला जारी

शुजालपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध मदिरा बिक्री और वसूली का मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार संबंधित अधिकारी की लापरवाही के कारण यह स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मदिरा माफिया कथित रूप से डायरियों के माध्यम से अवैध कारोबार संचालित कर रहे हैं। ठेकों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी अवैध और मिलावटी मदिरा का विक्रय किया जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

आरोप है कि इस ओर न तो जिला आबकारी विभाग का ध्यान है और न ही जिम्मेदार अधिकारी सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या संबंधित अधिकारियों को इन गतिविधियों की जानकारी नहीं है, या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि अवैध मदिरा बिक्री की सूचना दी जाती है, तो कार्रवाई से पहले ही संबंधित लोगों तक जानकारी पहुंच जाती है। परिणामस्वरूप जब तक अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, तब तक अवैध कारोबार करने वाले लोग वहां से जा चुके होते हैं।

यह स्थिति प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। यदि समय रहते इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके दुष्परिणाम और अधिक गंभीर हो सकते हैं।

शेष समाचार अगले अंक में जारी...

चाकूबाजी में युवक की मौत, दो आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, मंदसौर।

मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर रविवार देर रात हुई चाकूबाजी की घटना में घायल युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नरसिंहपुरा निवासी 19 वर्षीय अरुण पिता नानावटी बरगुण्डा पर दो युवकों ने चाकू से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी स्थिति नाजुक होने पर पहले जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए रतलाम शासकीय चिकित्सालय भेजा गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हमले के दौरान अरुण के पेट में गंभीर घाव हुए थे। चाकू लगने से उसके पेट के अंदरूनी अंग बाहर आ गए थे, जिससे उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल अन्यत्र भेजा, किंतु उसे बचाया नहीं जा सका।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय चार लोग मौजूद थे। इनमें से रोहित चौहान और युवराज माली ने अरुण पर चाकू से हमला किया और घटना के बाद वहां से फरार हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को नयाखेड़ा क्षेत्र के पास से पकड़ा तथा घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची, तो दोनों ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे और लंगड़ाते हुए चलते दिखाई दिए। पुलिस जांच में सामने आया है कि लगभग आठ माह पूर्व अरुण और युवराज के बीच विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि उस समय अरुण द्वारा युवराज को थप्पड़ मारने की घटना के बाद से दोनों के बीच रंजिश चली आ रही थी। इसके बाद एक माह पूर्व युवराज द्वारा अरुण को दूरभाष पर अपशब्द कहे जाने की बात भी सामने आई है, जिसे अरुण और उसके परिजनों ने सुना था।

तेज रफ्तार स्लीपर बस ट्रक में घुसी, पांच यात्री घायल

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम-इंदौर चार लेन मार्ग पर बिलपांक थाना क्षेत्र के सत्तागिरी फंटे के पास बुधवार सुबह लगभग 7 बजे एक तेज रफ्तार निजी स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। जोधपुर से इंदौर जा रही गजराज ट्रेवल्स की इस बस में सवार राजस्थान के बाड़मेर जिले के पांच यात्री घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे का कारण ट्रक का संचालन तंत्र अचानक खराब होना बताया जा रहा है, जिससे चालक को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पर मरम्मत कार्य के बाद बारीक गिट्टी भी पड़ी हुई थी, जिससे फिसलन की स्थिति बनी हुई थी। घटना के बाद सातरुंडा पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर पहुंचकर एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को रतलाम शासकीय चिकित्सालय (मेडिकल कॉलेज) में भर्ती कराया। वहीं क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस को मार्ग से हटाया गया और यातायात सुचारु किया गया।

जानकारी के अनुसार गजराज ट्रेवल्स की यह निजी स्लीपर बस जोधपुर से रतलाम होते हुए इंदौर जा रही थी। सत्तागिरी फंटे के मोड़ के पास अचानक आगे चल रहे ट्रक ने ब्रेक लगा दिए। तेज गति होने के कारण बस चालक नियंत्रण नहीं रख सका और बस सीधे ट्रक में जा टकराई। घटना के समय हल्की वर्षा भी हो रही थी, जिससे मार्ग और अधिक फिसलन भरा हो गया था। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और शीशे टूट गए। हादसे के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे।

इस दुर्घटना में बाड़मेर निवासी शेरू (पिता सोलाराम), अंबाराम (पिता धुलाराम), राजू (पिता उगमा), विशाल (पिता हेमराज)

और कृष्णा (पिता जयराम) घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार चार लेन मार्ग पर हाल ही में मरम्मत कार्य किया गया है, जिसमें डामर बिछाने के बाद बारीक गिट्टी डाली गई है। इससे मार्ग पर फिसलन बनी रहती है और आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।

सातरुंडा पुलिस चौकी प्रभारी लोकेश डाबर ने बताया कि ट्रक का संचालन तंत्र खराब होने के कारण चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके चलते पीछे से आ रही बस ट्रक से टकरा गई। घटना की जांच की जा रही है।

कांग्रेस पार्षद पर प्रकरण दर्ज, नगर निगम सम्मेलन में बयान पर विवाद

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम नगर निगम के बजट सम्मेलन में मंगलवार को वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी के बाद वार्ड क्रमांक 24 के कांग्रेस पार्षद सलीम बागवान के विरुद्ध स्टेशन रोड थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।

वार्ड क्रमांक 22 के भाजपा पार्षद एवं महापौर परिषद सदस्य विशाल शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 तथा 353(2) के अंतर्गत कार्रवाई की है। इस घटना के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच तनाव की स्थिति बन गई है तथा दोनों दलों द्वारा एक-दूसरे के पुतले जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया।

मंगलवार को आयोजित नगर निगम के बजट सम्मेलन में भाषण के दौरान कांग्रेस पार्षद सलीम बागवान द्वारा वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी से सदन में हंगामा हो गया। भाजपा पार्षदों ने उनसे माफी मांगने की मांग की, किंतु उन्होंने माफी नहीं मांगी। स्थिति बिगड़ने पर निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा ने लगभग आधे घंटे के लिए सम्मेलन स्थगित कर दिया।

पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि साधारण सम्मेलन के दौरान सभी पार्षद अपनी-अपनी बात रख रहे थे, तभी कांग्रेस पार्षद द्वारा महापुरुष वीर सावरकर के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे क्रांतिकारियों और देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायत के अनुसार इस प्रकार का वक्तव्य समाज में अशांति फैलाने वाला और दंडनीय है।

विवाद के बाद महापौर प्रहलाद पटेल के साथ भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस पार्षद सलीम बागवान सहित अन्य पार्षदों के पुतले निगम परिसर के बाहर जलाकर विरोध जताया। इसके बाद पुनः सम्मेलन शुरू होने पर कांग्रेस पार्षद वीर सावरकर से संबंधित इतिहास की प्रतियां लेकर सदन में विरोध जताने लगे।

इसी दौरान भाजपा की महिला पार्षदों ने कांग्रेस पार्षदों को चूड़ियां भेंट कर विरोध दर्ज कराया। इसके प्रत्युत्तर में कांग्रेस पार्षद यास्मिन शेरानी ने महापौर को चूड़ियां भेंट कर दीं, जिन्हें महापौर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा।

अंततः कांग्रेस पार्षदों ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल गए। इसके पश्चात कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी भाजपा सरकार के विरोध में पुतला दहन किया गया।

गुरु तेग बहादुर शैक्षणिक विकास समिति अध्यक्ष का निधन

माही की गूंज, रतलाम।

गुरु तेग बहादुर शैक्षणिक विकास समिति के अध्यक्ष गुरनाम सिंह डंग (65) का कुछ दिनों की बीमारी के बाद मंगलवार रात निधन हो गया। शिक्षा और सामाजिक कार्यों में सक्रिय गुरनाम सिंह डंग पिछले 16 वर्षों से समिति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। उनका अंतिम संस्कार 8 अप्रैल (बुधवार) को भक्तन की बावड़ी स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा। उनके निधन के कारण समिति द्वारा संचालित दोनों विद्यालयों में बुधवार को अवकाश घोषित किया गया है।

गुरनाम सिंह डंग शिक्षा जगत और सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। वे मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ केंद्रीय गुरु सिंह सभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, जिसके चलते मंगलवार रात उनका निधन हो गया। उनके परिवार में एक भाई सतपाल सिंह, दो पुत्र अंकित डंग व अर्पित डंग तथा एक पुत्री सोनल हैं।

गुरनाम सिंह डंग की अंतिम यात्रा 8 अप्रैल (बुधवार) को दोपहर 1 बजे राज गार्डन के सामने बरबड़ रोड स्थित उनके निवास से निकलेगी। इसके पश्चात भक्तन की बावड़ी स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

समिति द्वारा शोक व्यक्त करते हुए संचालित दोनों विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत गुरु बहादुर अकादमी तथा गुरु तेग बहादुर सार्वजनिक विद्यालय में 8 अप्रैल को पूर्ण अवकाश रहेगा।

जल जीवन मिशन की टंकी शुरू होने से पहले ही रिसाव, निर्माण गुणवत्ता पर सवाल

माही की गूंज, मंदसौर।

मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम हरसोल में ग्राम पंचायत भवन के समीप जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित पेयजल टंकी प्रारंभ होने से पहले ही रिसाव का शिकार हो गई है। टंकी से चारों ओर पानी झरने की तरह बहता दिखाई दे रहा है। लगभग 2500 की आबादी के लिए बनाई गई डेढ़ लाख गैलन क्षमता की इस टंकी के रिसाव के कारण समीप रहने वाले किसान भेरूलाल प्रजापति के घर तक पानी पहुंच गया, जिससे उनकी गेहूं और लहसुन की फसल को नुकसान हुआ है।

लाखों रुपये की लागत से निर्मित इस टंकी की गुणवत्ता को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि टंकी अभी प्रारंभ भी नहीं हुई और उसमें से पानी रिसने लगा, जो निर्माण कार्य में लापरवाही और घटिया सामग्री के उपयोग की ओर संकेत करता है।

मामले की जानकारी मिलने पर मंडल अध्यक्ष गजेन्द्रसिंह चूंडावत ने ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा को अवगत कराया। इसके बाद जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अजित कुमठ सहित अन्य जनप्रतिनिधि हरसोल पहुंचे और मौके का निरीक्षण कर ग्रामीणों से चर्चा की।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि टंकी का

निर्माण निम्न गुणवत्ता की सामग्री से किया गया है, जिससे भविष्य में इसके गिरने की आशंका भी बनी हुई है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अनिल शर्मा ने अनुविभागीय अधिकारी स्वाति तिवारी को पूरे प्रकरण की जानकारी देकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही प्रभावित किसान भेरूलाल प्रजापति को फसल नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग की गई है।

जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अजित कुमठ ने कहा कि क्षेत्र में कई निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सड़कों, पेयजल टंकियों और चिकित्सालय निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसे कमीशन आधारित व्यवस्था बताया।

घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो।

निरीक्षण के दौरान गजेन्द्रसिंह चूंडावत, भेरूलाल प्रजापति, मोहनलाल वर्मा, मदनलाल मेघवाल, शांतिलाल मेघवाल, आबिद मंसूरी, सुखलाल टेलर, आबिद पठान, दीपक प्रजापति, फजल मंसूरी, मुकेश प्रजापति, बसंतीलाल मालवीय, भारतसिंह चूंडावत और गोपाल वर्मा सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

युवक से 29 तलवारें बरामद, अवैध हथियार आपुर्ति का खुलासा

माही की गूंजए खंडवा।

खंडवा में अवैध हथियारों के विरुद्ध सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा के एक युवक को 29 धारदार तलवारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी रेलगा?ी के माध्यम से बोरियों में तलवारें भरकर शहर लाता था और विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी आपूर्ति करता था। आरोपी ने किन.किन लोगों को तलवारें बेचींए इसकी जानकारी के लिए पुलिस द्वारा उसके संपर्क विवरण का परीक्षण किया जा रहा है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर ने बताया कि 7 अप्रैल को कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण आर्य को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति बमनगांव रोड स्थित पुलिया के पास रेलवे बाहरी क्षेत्र में तलवारें बेचने की फ़िराक में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस दल ने घेराबंदी कर आरोपी को पक? लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम प्रदीप ;30 वर्षद्धए निवासी कैथल बताया। उसके पास मौजूद बोरे की तलाशी लेने पर 29 धारदार तलवारें बरामद की गईं। आरोपी इनके संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध सिटी कोतवाली थाने में शस्त्र अधिनियम की धारा 25;1.बीद्ध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह हरियाणा से तलवारों की खेप बोरियों में भरकर रेलगा?ी से लाता था और सीट के नीचे छिपाकर खंडवा तक पहुंचता था। यहां वह विभिन्न क्षेत्रों में 500 से 600 रुपये प्रति तलवार के हिसाब से उन्हें बेचता था। प्रारंभ में वह नमूने के रूप में कुछ तलवारें लाया थाए बाद में ब?ी मात्रा में आपूर्ति करने लगा।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पूर्व में भी कई बार खंडवा आकर इस प्रकार की आपूर्ति कर चुका है। उसके विरुद्ध पुराना रेलवे स्टेशन थाना क्षेत्र में भी प्रकरण दर्ज होना बताया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा जिले को जानबूझकर निशाना बनाए जाने की आशंका हैए क्योंकि यहां धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील अवसरों पर धारदार हथियारों के उपयोग की घटनाएं पूर्व में सामने आती रही हैं।

फ़िलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे आपूर्ति तंत्र की जानकारी जुटा रही है। साथ ही तलवार खरीदने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अनुसार आरोपी के दूरभाष संपर्क विवरण का गहन परीक्षण किया जा रहा है।

इमली तोड़ने पेड़ पर चढ़ा बालक 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आया

माही की गूंज, कुक्षी।

इमली तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा एक 13 वर्षीय बालक 11 केवी उच्चदाब विद्युत लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। धार जिले की कुक्षी तहसील में बुधवार सुबह हुई इस घटना में बालक की कमर और पैर का हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। उसे गंभीर अवस्था में बड़वानी जिला चिकित्सालय भेजा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लिंगवा में सुबह लगभग 11 बजे बालक सुखा पिता अजय (13) इमली तोड़ने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा था। पेड़ के समीप से ही 11 केवी की विद्युत लाइन गुजर रही थी। असावधानी के कारण बालक का शरीर विद्युत तार से स्पर्श हो गया, जिससे उसे तेज झटका लगा और वह पेड़ में ही फंसकर अचेत हो गया।

घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए जोखिम के बावजूद रस्सी की सहायता से बालक को सावधानीपूर्वक नीचे उतारा। विद्युत करंट की चपेट में आने से उसकी कमर और पैर गंभीर रूप से झुलस गए हैं।

ग्रामीणों द्वारा तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई, जिसके बाद बालक को निसरपुर अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला चिकित्सालय बड़वानी भेज दिया।

घटना की सूचना मिलते ही निसरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। फिलहाल बालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है और जिला चिकित्सालय में उसका उपचार जारी है।

भूकंप के झटके, 3.4 तीव्रता दर्ज

माही की गूंज, बड़वानी।

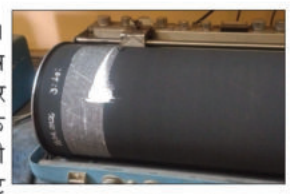

बड़वानी जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहिपुरा में बुधवार दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। लगभग दो मिनट तक धरती में हल्का कंपन महसूस होने की बात सामने आई है। झटके महसूस होते ही ग्रामीण घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए।

ग्रामीणों के अनुसार झटकों के दौरान घरों में रखे बर्तन, फर्नीचर और पंखे हिलते हुए दिखाई दिए। ग्राम मोहिपुरा निवासी लोकेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वे दोपहर में घर पर विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक तेज झटका महसूस हुआ। इसके बाद वे तुरंत बाहर निकले और आसपास के लोगों से जानकारी लेने पर भूकंप की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का अनुभव पहली बार हुआ है। इंदिरा सागर विद्युत केंद्र की भूकंप वेधशाला तथा राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर भी दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई है। जिला मुख्यालय पर संचालित भूकंप केंद्र में स्थापित सिस्मोमीटर यंत्र में भी यह कंपन 3.4 तीव्रता का दर्ज किया गया। केंद्र के संचालक हुकुम कुमार ने बताया कि सूक्ष्म भूकंप मापन यंत्र 24 घंटे संचालित रहता है और प्रतिदिन प्रातः नर्मदा नगर (पुनासा, खंडवा) स्थित केंद्र से रिपोर्ट जारी की जाती है। बुधवार दोपहर को अंजड़ क्षेत्र में दर्ज इस हलचल की तीव्रता 3.4 मापी गई। यह यंत्र लगभग 40 से 50 किलोमीटर क्षेत्र में भू-कंपन की तीव्रता दर्ज करने में सक्षम है।

संत की समाधि से शव निकालने की मांग, मौत पर उठे सवाल

माही की गूंज, ओंकारेश्वर।

ओंकारेश्वर (ज्योतिर्लिंग नगरी) में उदासीन अखाड़े से जुड़े संत ब्रजराज पुरी महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु का मामला विवादों में घिर गया है। आश्रम से जुड़े लोगों द्वारा हृदयाघात से मृत्यु बताए जाने और जल्दबाजी में समाधि दिए जाने के बाद खाचरोद से आए महंत, संत समाज, हिंदू महासभा तथा परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को समाधि से निकालकर शव परीक्षण कराने की मांग की है।

हिंदू महासभा के आवेदन पर कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने मामले की जांच के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए हैं, जबकि मांधाता थाना पुलिस ने निकट संबंधियों की औपचारिक शिकायत न होने का हवाला देते हुए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

संत की मृत्यु के कारणों को लेकर अलग-अलग बातें सामने आने से संदेह और गहरा गया है। आश्रम से जुड़े लोगों ने हृदयाघात से मृत्यु की जानकारी दी, जबकि खाचरोद से आए उदासीन अखाड़े के महंत ओंकारदास उदासीन ने फांसी लगाने की सूचना मिलने का दावा किया है। उनका कहना है कि उनके ओंकारेश्वर पहुंचने से पहले ही संत को जल्दबाजी में समाधि दे दी गई, जबकि परंपरा के अनुसार दूर-दराज से आने वाले संतों की प्रतीक्षा की जाती है।

महंत ओंकारदास ने यह भी आरोप लगाया कि संत के गले में पहनी सोने की चेन, रुद्राक्ष माला, दूरभाष यंत्र और नकदी मौके पर नहीं मिली। उन्होंने मांधाता थाने में आवेदन देकर शव को समाधि से निकालकर शव परीक्षण कराने की मांग की है।

संत के भतीजे संदीप रघुवंशी (निवासी धार) ने भी पुलिस को आवेदन सौंपते हुए कई प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि आश्रम में मौजूद व्यक्ति द्वारा हृदयाघात की बात कही गई, लेकिन संत के सामान के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि आश्रम में मौजूद एक व्यक्ति के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए, जिससे हत्या की आशंका और प्रबल हो गई है।

इस प्रकरण में 73 एकड़ भूमि विवाद का पहलू भी सामने आया है। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों के अनुसार संत ब्रजराज पुरी महाराज ने पूर्व में इस भूमि विवाद का उल्लेख किया था। आरोप है कि उक्त भूमि को कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अन्य नाम पर दर्ज करा लिया गया। संत समाज इस विवाद को भी संदेह की दृष्टि से देख रहा है।

हिंदू महासभा के सदस्यों ने कलेक्टर को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच और शव परीक्षण की मांग की है। कलेक्टर द्वारा यह आवेदन पुलिस अधीक्षक को भेजकर जांच के निर्देश दिए गए हैं।

मांधाता थाना प्रभारी अनोक सिंह सिंदिया का कहना है कि अब तक संत के किसी निकट संबंधी की औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। उनके अनुसार संबंधित पक्षों की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कब पुन: शुरू होगी वरिष्ठ नागरिकों की रेल यात्रा में छूट?

मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान दुनिया के अनेक देशों में तरह तरह के अभूतपूर्व फैसले लिये गये थे। प्रायः ऐसे फैसलों का मकसद कोरोना महामारी के संक्रमण को यथासंभव रोकना था। इसी दौरान पूरे विश्व में हवाई यातायात तक ठप्प हो गया था। अनेक देशों में लॉक डाउन लगा दिया गया था। कल-कारखाने सभी प्रकार के यातायात, व्यवसाय, उद्योग बाजार आदि सभी बंद कर दिये गये थे। भारत भी उन्हीं देशों में एक था जहाँ पूर्ण लॉक डाउन लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं 24 मार्च 2020 की रात को पहले चरण के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। 25 मार्च 2020 की मध्यरात्रि से लागू हुआ प्रथम चरण का यह पूर्ण लॉकडाउन पहले तो केवल 21 दिनों का बताया गया था परन्तु बाद में भी इसे कई चरणों में आगे बढ़ाया गया था। इसी पूर्ण लॉकडाउन के दौरान रेल सहित देश की सभी यातायात सुविधाओं को पूर्णतः स्थगित कर दिया गया था। कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद भारतीय रेलवे ने 12 मई से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेनों को फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम 15 विशेष ट्रेनों के द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को असम, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू, झारखंड,कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा के प्रमुख शहरों से जोड़ा गया था। बाद में धीरे धीरे इनका विस्तार किया गया।

भारत सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाते हुये वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में रेल टिकट पर मिलने वाली आंशिक छूट को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को समाप्त करते समय सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया था कि ÷अनावश्यक यात्रा रोकने÷ के लिये यह छूट समाप्त की गयी है। परन्तु आज पूरे छः वर्ष बीत जाने के बाद भी जबकि देश भर में ट्रेन सेवाएं लगभग सामान्य हो चुकी हैं, यह छूट आज तक बहाल नहीं हुई है। गौरतलब है कि उसी दौरान प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि इतनी बड़ी आपदा, भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। भारत ने आपदा को, अवसर में बदल दिया है । रेल विभाग ने भी इसी आपदा में अवसर देखते हुये कोरोना काल की आड़ में कई ऐसे निर्णय ले डाले जो सरकार के लिये भले ही लाभदायक रहे हों परन्तु रेल यात्रियों के लिये तो हरगिज नहीं थे। मिसाल के तौर पर अनेक पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन बताकर कहीं स्टॉपेज कम कर दिये गये तो कहीं किराया बढ़ा दिया गया। कई ट्रेन स्थाई रूप से कैंसिल कर दी गयी तो कई ट्रेन के रुट बदल दिये गये। इनमें से कोरोना काल के समय किये गये कुछ परिवर्तन तो यथापूर्व किये गये परन्तु कुछ कोरोना काल समाप्त होने के बावजूद आज तक वैसे ही हैं। जैसे कि कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में रेल टिकट पर मिलने वाली आंशिक छूट को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना।

सवाल यह है कि जब यह छूट समाप्त करते समय ÷अनावश्यक यात्रा रोकने÷ जैसा तर्क दिया गया था तो आज तक उस छूट को पुनः लागू क्यों नहीं किया गया ? जबकि अब न केवल कोरोना काल के पूर्व की लगभग सभी ट्रेन्स चल रही हैं बल्कि अनेक नई ट्रेन्स भी पटरियों पर दौड़ने लगी हैं? गौरतलब है कि भारतीय रेल ने छात्र, दिव्यांगजन, रोगी, स्वतंत्रता सेनानी, युद्ध विधवाएँ जैसी कुल 53 श्रेणियों में विभिन्न स्तर पर छूट दी थी। इन्हीं में वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली टिकट छूट की सुविधा विभिन्न चरणों में 1985 में शुरू की गई थी। अगस्त 2001 से इसे स्वैच्छिक बना दिया गया अर्थात वरिष्ठ नागरिक चाहें तो छूट ले सकते थे। लेकिन यात्रा के दौरान छूट लेने वालों को अपनी आयु का कोई न कोई प्रमाण जैसे आधार, पैन कार्ड या पासपोर्ट आदि यात्रा के समय अपने साथ रखना अनिवार्य कर दिया गया था। इस सुविधा का लाभ देश के बुजुर्गों ने 35 वर्षों तक उठाया परन्तु स्वयं को लोक हितकारी बताने का ढिंढोरा पीटने वाली मोदी सरकार ने इसे कोरोना की आड़ में समाप्त कर दिया। जो सरकार छूट समाप्त करते समय ÷अनावश्यक यात्रा रोकने÷ जैसा तर्क दे रही थी वही सरकार अब इसे सरकार पर ÷वित्तीय बोझ÷ मान रही है। सरकार का तर्क है कि रेलवे पहले से ही भारी घाटे में चल रही है। रेल मंत्री संसद में बता भी चुके हैं कि रेलवे सभी यात्रियों को औसतन 45: सब्सिडी दे रही है। गोया प्रत्येक यात्री को पहले से ही काफी राहत मिल रही है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि सरकार अनावश्यक यात्रा रोकने जैसे उपाय कर देश के बुजुर्गों से अब तक दस हजार करोड़ से अधिक रूपये कमा चुकी है।

निर्मल रानी

इसी सन्दर्भ में इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि बुजुर्गों की रेल यात्रा छूट समाप्त करने वाली यही सरकार जब चाहती है और जहाँ से चाहती है विभिन्न तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा हेतु विशेष ट्रेन चला देती है। जब चाहती है चुनावी राज्यों के लिये स्थानीय प्रवासियों हेतु विशेष ट्रेन चलाकर उन्हें मतदान करने हेतु निःशुल्क भेजती है। गोया अपने वोट बैंक साधने के लिये तो सरकार तत्पर रहती है परन्तु इसी सरकार के पास न तो कोरोना काल की शुरुआत में इन्हीं प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों व शहरों तक भेजने के लिये कोई ट्रेन थी न ही आज उन ट्रेन्स पर चलने वाले बुजुर्गों के लिये पूर्व में मिलने वाली छूट ? हालाँकि कभी कभार अपुष्ट सूत्रों से यह खबर सुनाई देती है कि शायद सरकार पुनः यह छूट देने पर विचार कर रही है। परन्तु इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। विपक्षी सांसदों ने इसे बुजुर्गों के साथ अन्याय÷ बताते हुये लोकसभा में भी कई बार सवाल उठाए परन्तु सत्ता पक्ष ने वित्तीय कारण÷ देकर यह सुविधा शुरू करने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग संगठनों में भी इसे लेकर काफी नाराजगी व गहरी निराशा है। इसी लिये देश यह सवाल कर रहा है कि जब सांसदों विधायकों को आजीवन पेंशन देने के लिये वित्तीय कारण÷ आड़े नहीं आते तो आखिर सरकार बुजुर्गों को ट्रेन में छूट क्यों नहीं दे रही? वरिष्ठ नागरिकों को आज भी इस बात की आस है कि आखिर रेल यात्रा में मिलने वाली छूट कब शुरू होगी?

नगरीय निकायों की कर वसूली में 11 प्रतिशत वृद्धि, उज्जैन सबसे आगे

माही की गूंज, उज्जैन।

प्रदेश के नगरीय निकायों की कर वसूली में इस वर्ष 11.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, हालांकि राजधानी भोपाल और इंदौर की वृद्धि दर अपेक्षाकृत धीमी रही। 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भोपाल में मात्र 2.17 प्रतिशत तथा इंदौर में 5.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वहीं दूसरी ओर उज्जैन में कर वसूली में 47 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यहां संपत्ति कर, जल कर और भवन अनुमति शुल्क में मामूली वृद्धि रही, जबकि पार्किंग शुल्क, व्यापार लाइसेंस और कॉलोनी विकास शुल्क जैसे अन्य मदों में लगभग 500 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई।

मुरैना और बुरहानपुर जैसे छोटे शहरों ने भी संपत्ति कर सहित अन्य करों में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज कर बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर प्रदेश के नगर निगमों ने 2501.26 करोड़ रुपये कर वसूला, जो पिछले वर्ष के 2252.16 करोड़ रुपये से अधिक है।

उज्जैन में पिछले वर्ष के 47 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष संपत्ति कर से 55 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। वहीं जल कर 6.70 करोड़ रुपये से घटकर 3 करोड़ रुपये तथा भवन अनुमति से प्राप्त आय 12 करोड़ रुपये से घटकर 3 करोड़ रुपये रह गई है।

इसके विपरीत अन्य करों से प्राप्त आय 10 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 60 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस श्रेणी में पार्किंग शुल्क, व्यापार लाइसेंस, अग्नि लाइसेंस, सीवरेज कर, कचरा संग्रहण कर और विज्ञापन शुल्क शामिल हैं। महाकाल विस्तार के बाद शहर में बढ़ी आर्थिक गतिविधियों को इस वृद्धि का प्रमुख कारण माना जा रहा है।

नगर निगम के अपर आयुक्त पवन सिंह के अनुसार, उज्जैन का कुल कर संग्रहण 131 करोड़ रुपये रहा है और शहर में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

तेज रफ्तार कार घर और दुकान में घुसी, एक युवक घायल

माही की गूंज, आलीराजपुर।

आलीराजपुर जिले के ग्राम छकतला में बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे एक मकान और दुकान में जा घुसी। इस हादसे में दुकान के भीतर मौजूद अक्षय बंदोड चौहान घायल हो गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर क्षतिग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया है।

घटना के तुरंत बाद घायल अक्षय को उपचार के लिए मध्य प्रदेश की सीमा से लगे बोडेली स्थित चिकित्सालय भेजा गया, जहां चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना का एक दृश्य भी सामने आया है, जिसमें कार दुकान का शटर तोड़ते हुए भीतर घुसती दिखाई दे रही है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार छकतला से अड्डा की ओर जा रही थी। दुर्घटना का मुख्य कारण चालक की लापरवाही और तेज गति बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया है तथा फरार चालक की तलाश की जा रही है।

आगर रोड हत्याकांड में तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन के आगर रोड पर हुए युवक की हत्या के मामले में चिमनगंजमंडी पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह हत्या लिफ्ट मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद की गई थी। पुलिस ने इस प्रकरण का खुलासा महज चार घंटे में कर दिया।

यह घटना 2 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 8 बजे सामने आई, जब आगर रोड किनारे एक युवक का शव रक्तरंजित अवस्था में मिला। मृतक की पहचान बेगमबाग कॉलोनी निवासी भुरु उर्फ आरिफ के रूप में हुई। पुलिस ने विधि विज्ञान दल और छायाकार की सहायता से घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में मोनू उर्फ दीपांशु (22), लक्की (22) और रेहान मंसूरी (20) शामिल हैं। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर उनका जुलूस भी निकाला। इससे पहले एक आरोपी को पकड़ा जा चुका था, जिसके बाद अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। शेष आरोपियों की तलाश जारी है।

जांच के दौरान प्राप्त दृश्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई। पूछताछ में सामने आया कि 1 अप्रैल की रात लिफ्ट मांगने को लेकर विवाद हुआ था, जो बढ़कर हिंसक हो गया। इसके बाद आरोपियों ने मिलकर युवक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पा प्रजापति और थाना प्रभारी गजेंद्र पचोरिया सहित पुलिस दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम में लक्ष्मण उईके, लिबिन खेस, महेश बैस, मनोज कटारिया सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन में बुधवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा संकुल भवन स्थित कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। शहर एवं जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली निकालकर विरोध दर्ज कराने पहुंचे।

रैली की शुरुआत देवास रोड स्थित स्विमिंग पूल चौराहा से हुई, जिसमें महेश परमार, दिनेश जैन बोस, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, सुरेंद्र मरमट, रवि राय सहित कई नेता शामिल हुए। रैली कोठी रोड होते हुए संकुल भवन पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान विधायक अपने ऊपर नारे लिखकर प्रदर्शन में शामिल हुए, जिनमें किसानों की फसल खरीदी और दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग प्रमुख रही।

विधायक महेश परमार ने आरोप लगाया कि फसल खरीदी के मामले में किसानों को बार-बार तिथियां दी जा रही हैं और उन्हें मंडी में गेहूं 2018 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है।

प्रदर्शन में शहर एवं प्रदेश किसान कांग्रेस के पदाधिकारी धर्मेंद्र जी, प्रभारी चंद्र भाई सहित जिलेभर से आए किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई।

परीक्षा प्रश्न को लेकर विवाद, विश्वविद्यालय ने जांच के दिए निर्देश

माही की गूंज, उज्जैन।

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में बीकॉम और बीसीए तृतीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम की परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को आयोजित परीक्षा में पूछा गयाकृ अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसके साथ चार विकल्प दिए गए थे, जिनमें सोमेश्वर, खुदा, शक्तिवान और दंड देने वाला शामिल थे।

इस प्रश्न को लेकर विभिन्न संगठनों ने आपत्ति जताते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। परीक्षा के बाद उज्जैन सहित रतलाम में भी विरोध के स्वर सामने आए हैं।

मामले में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक रितेश माहेश्वरी ने कहा कि इस प्रकार का प्रश्न पूछना उचित नहीं है और संबंधित जिम्मेदार के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा।

विवाद बढ़ने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कुलसचिव अनिल शर्मा ने बताया कि प्रकरण को परीक्षा समिति को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि आधार पाठ्यक्रम में विभिन्न धर्मों से जुड़े प्रश्न शामिल किए जाते हैं, किंतु इस प्रकार का प्रश्न अपेक्षित नहीं है।

वहीं कुलपति अर्पण भारद्वाज ने परीक्षा नियंत्रक से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही परीक्षा विभाग की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि यदि प्रश्न को निरस्त किया जाता है तो विद्यार्थियों को अंक किस प्रकार प्रदान किए जाएंगे।

फिलहाल मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

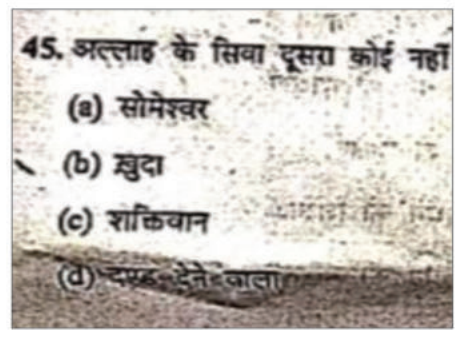

शादी विवाद में काका ने भतीजे पर तीर चलाया, युवक गंभीर घायल

माही की गूंज, आलीराजपुर।

आलीराजपुर जिले के ग्राम सूखी बावड़ी में सोमवार रात एक विवाह समारोह के दौरान हुए विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पारिवारिक कहासुनी के बीच-बचाव में आए भतीजे रवि सस्तीया पर उसके सगे काका कमल सस्तीया ने तीर से हमला कर दिया।

तीर सीधे युवक के पेट में जा धंसा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। परिजनों ने तत्काल घायल रवि को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने तक तीर उसके पेट में ही फंसा हुआ था। चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए दाहोद भेजा गया है, जहां उसका उपचार जारी है।

घायल के भाई राजेश सस्तीया के अनुसार परिवार के दो सदस्यों के बीच विवाद चल रहा था। इसी दौरान रवि विवाद शांत कराने के लिए बीच में आया, तभी आवेश में आकर कमल सस्तीया ने उस पर तीर चला दिया। घटना के बाद विवाह स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी काका कमल सस्तीया को गिरफ्तार कर लिया। घायल को चिकित्सालय पहुंचाने में एम्बुलेंस कर्मी जवसिंह बामनिया और चालक महेश मंडलोई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सामुदायिक पुलिसिंग का नया मॉडल तैयार, सिंहस्थ में जनता की भागीदारी से मजबूत होगी सुरक्षा

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन पुलिस ने आगामी सिंहस्थ महापर्व एवं अन्य बड़े धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग का नया मॉडल तैयार किया है। मंगलवार को आयोजित सामुदायिक पुलिसिंग क्षमता वर्धन कार्यशाला में इस मॉडल को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें आम जनता की सीधी भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया।

इस मॉडल के अंतर्गत सिंहस्थ में 'सिंहस्थ रक्षा साथी' और स्वयंसेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये स्वयंसेवक पुलिस और प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करेंगे, जिससे भीड़ प्रबंधन, सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी।

प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक स्वयंसेवकों को जोड़ने के लिए कई सुविधाएं प्रस्तावित की गई हैं। सेवा देने वाले स्वयंसेवकों को मानदेय, आधिकारिक प्रमाण-पत्र तथा आयोजन के दौरान ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि युवाओं और स्थानीय नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए उज्जैन जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राकेश गुप्ता ने सिंहस्थ जैसे विशाल आयोजनों में नगर रक्षा समिति के प्रभावी उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए जनता के साथ समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के 26 जिलों से नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से अपराध नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन तथा जनभागीदारी बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया।

यह मॉडल विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें पहली बार बड़े स्तर पर स्वयंसेवक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। नगर रक्षा समिति को सक्रिय भूमिका देते हुए पुलिस और आमजन के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा, जिससे बड़े आयोजनों में त्वरित सहायता प्रणाली विकसित हो सके।

कार्यशाला के अंत में अधिकारियों ने इस मॉडल को आगामी सिंहस्थ की तैयारियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

शराब माफिया बाकलिया ग्रुप ने अपने शाम, दाम, दंड, भेद को ऐसा भेदा कि 2 सौ 12 करोड़ की 13 शराब दुकान अधर में

गुजरात बॉर्डर की माण्डली, वट्ठा के साथ 8 देशी कंपोजिट व 5 विदेशी कंपोजिट शराब दुकानों में से कुछ पर 6 गुना बोली के साथ दुकान अपने कब्जे में कर बाकलिया अपनी बल्ले-बल्ले कर रहा

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मिल मंसुरी

झाबुआ जिले के साथ मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में शराब दुकानों का संचालन करने वाला बाकलिया ग्रुप झाबुआ जिले में कुछ वर्षों से अपना एकाधिकार जमा कर बैठा है। उसी के साथ प्रशासनिक संरक्षण व राजनीतिक सहयोगियों के चलते जिले में अपने आतंक का भी परिचय कई बार यह बाकलिया दे चुका है।

अब बाकलिया ग्रुप के बारे में कहा जाने लगा है कि, जो आबकारी विभाग व सरकार को नुकसानी बताकर दुकान सस्ती करवाने का षड्यंत्र रचता है, परंतु अगर बाकलिया ग्रुप को झाबुआ जिले में शराब दुकाने नहीं मिले तो वह खाना-पीना भी छोड़ दे। इसलिए बाकलिया ग्रुप का प्रयास रहता है कि, कैसे से भी करके दुकाने कम रेट में हो और उसे ही वह दुकाने मिले। सरकार अगर एक-एक दुकान देने की पॉलिसी बनाएं उसमें जो दुकाने सस्ती हो उसे अत्याधिक भाव में लेकर तथा महंगी दुकानो को अधर में छोड़ अपना उल्लू साध सरकार को चूना लगाने में कोई कसर बाकलिया ग्रुप नहीं छोड़ता है।

इस वर्ष 2026-27 हेतु जिले की 34 देशी-विदेशी कंपोजिट शराब दुकानों का कुल आबकारी राजस्व 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ करीब 345 करोड रुपए का राजस्व था। वही बाकलिया ग्रुप ने अपने कर्मचारियों के नाम से बनाए फर्म के नाम से राणापुर एवं पिटोल समूह की करीब 90 करोड़ की 8 शराब दुकाने प्रथम व द्वितीय राउंड में ले चुका था। जिसके बाद जिले में दो गुजरात सीमा से सट्टी विदेशी कंपोजिट शराब दुकान के साथ 18 विदेशी एवं 8 देशी कंपोजिट शराब दुकान कुल 26 शराब दुकानों का 7 वे राउंड के बाद 27 मार्च को 8 वें राउंड में नीलामी होनी थी। जिसमें 15 प्रतिशत राशि घटाकर 2 सौ 60 करोड़ 47 लाख के राजस्व के साथ नीलामी प्रक्रिया की गई थी। जिसमें बाकलिया ग्रुप ने अपने साम, दाम, दंड, भेद के साथ माफियाई आतंक का परिचय भी दिया। और अन्य लोगों को एकल प्रणाली के तहत शराब दुकान के फार्म भरने पर उनके घरों पर आबकारी व पुलिस भेज कर धमकाने का प्रयास किया। वहीं ऑनलाइन बिडिंग में जो बाहरी ठेकेदार भी अपने टेंडर के साथ शामिल हुए थे। उन्हें भी पटकनी देते हुए 8 देशी कंपोजिट जिसमें मेघनगर, थांदला, खवासा, कल्याणपुर, रायपुरिया, सारंगी, बामनिया, पेटलावद जिनका कुल मूल्य 17 करोड़ 68 लाख के करीब सस्ती दुकाने थी उन्हें ऊंची बोली पर ले ली गई।

इसी तरह 5 विदेशी कंपोजिट शराब दुकान जिसमें झकनावदा, माण्डली, वट्ठा, भगोर व करवड की दुकाने ली गई। जिसका 30 करोड़ 70 लाख की निर्धारित राजस्व था। कुल 13 दुकाने एवं 8 दुकाने पूर्व में कुल 21 दुकाने लेकर पूरे जिले पर अपना कब्जा जमा लिया है। इन 13 दुकानों में बता दे कि, भगोर की विदेशी कंपोजिट शराब दुकान का 1 करोड़ 25 लाख के करीब थी। जिसे 6 गुना से अधिक बोली लगाकर 7 करोड से अधिक में ली गई। वहीं थांदला की क्रमांक 2 देशी कंपोजिट शराब दुकान 3 करोड़ 52 लाख के करीब की दुकान थी उसे करीब साढे 8 करोड रुपए में ली गई। इसी तरह जिले में जहां शराब दुकाने हैं वहां पर देशी व विदेशी की कंपोजिट 21 शराब दुकाने लेकर अपना एकाधिकार जमा लिया है।

बता दे कि, जो 26 शराब दुकाने 2 सौ 60 करोड़ से अधिक के मूल्य की दुकाने थी उसमें से 13 दुकाने जिसमें 8 देशी कंपोजिट व 5 वट्ठा, मांडली सहित इन दुकानों का मूल्य 48 करोड़ के करीब का था। इन शराब दुकानों पर कुछ में 5-6 गुना तो कुछ में 25-30 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ शराब दुकाने ले ली गई। वहीं मेघनगर, थांदला, खवासा, कल्याणपुरा, रायपुरिया, सारंगी, बामनिया, पेटलावद, झाबुआ बस स्टैंड, काली देवी, पारा, मदरानी, काकनवानी की कुल 13 विदेशी कंपोजिट शराब दुकान जिनका कुल मूल्य 2 सौ 12 करोड़ से अधिक है अधर में रख दी और शासन की नीति में सेंध लगाकर आधे दाम में ही पूरे जिले पर अपना कब्जा कर लिया है।

उदाहरण के लिये बता दे कि, शासन ने देशी पर विदेशी व विदेशी पर देशी कंपोजिट शराब दुकान के साथ दोनों शराब बेचने का प्रावधान पिछले दो वर्षों से किया गया है। ऐसे में जहां पर देशी कंपोजिट शराब दुकान हैं वहा विदेशी कंपोजिट की तुलना में बहुत सस्ती है। जैसे कि, मेघनगर में देशी कंपोजिट करीब 3 करोड़ 66 लाख की दुकान थी तो वहीं विदेशी कंपोजिट दुकान 27 करोड़ 11 लाख के करीब थी। उसी तरह थान्दला में देशी कंपोजिट 3 करोड़ 52 लाख, विदेशी कंपोजिट 15 करोड़ 84 लाख के करीब थी।

ऐसे में 27 मार्च को ली गई 13 देशी एवं विदेशी शराब दुकानों का मूल्य 48 करोड़ के करीब था। तो वही बची हुई 13 विदेशी कंपोजिट शराब दुकानों का मूल्य 2 सौ 12 करोड़ था। ऐसे में 2 सौ 12 करोड़ की 13 दुकाने नहीं ली गई। 31 मार्च से अब तक भी नीलामी प्रक्रिया चल रही है जिसमें से 2-3 दुकानो पर बहुत कम का टेंडर डालने का प्रयास किया गया है।

वहीं बाकलिया ग्रुप का यह षड्यंत्र है कि, बची हुई 2 सौ 12 करोड़ की दुकाने 100 करोड़ के अंदर मिल जाए। फिलहाल में बची हुई 13 खाली दुकानों पर आबकारी की खाकी वर्दी बेठी है। तो वहीं जानकारी रखने वाले बताते हैं कि, बाकलिया ग्रुप के गुर्गे इन खाली दुकानों के पीछे 2-2 पहिया वाहनो से शराब की पेटिया ले जाते हैं और आगे आबकारी की खाकी वर्दी पेहरा देती है और पीछे बाकलिया ग्रुप के गुर्गे करोडो मूल्य की दुकानों पर अवैध रूप से अपनी अवैध शराब बेच रहे हैं।

आगे भी निलामी चालु है ऐसे मे यह 13 दुकाने कितने कम में जाती है या आबकारी इन दुकानो पर शराब बेचेगी यह बाद में ही पता चलेगा।

जिले में नहीं है एक भी अंग्रेजी माध्यम की शासकीय हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी

सीएम राईज या सांदीपनि के नाम पर सिर्फ भवन, इसके अलावा सब शुन्य...!

माही की गूंज, झाबुआ।

एक कहावत बड़ी मशहूर है कि, ''अपनी ढपली अपना राग''। यह कहावत इन दिनों जिला शिक्षा विभाग और प्रशासन पर खूब सटीक साबित हो रही है। वैसे तो जिले में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इस स्तर के सुधार में पिछले कई दशकों से सफलता के कागजी घोड़े पूरी रफ्तार से जिला जनजातीय कार्य विभाग, शिक्षा विभाग और प्रशासन दौड़ाते नजर आ रहा है। आजादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी जनजातीय कार्य विभाग, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन का फोकस है कि, प्राथमिक शिक्षा से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल सत्र शुरू होते ही कई तरह की कवायदें प्रशासन शुरू करता है। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जाते है। पलायन पर गए बच्चों को शाला तक लाने और शाला त्यागी बच्चों को फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के सरकारी आंकड़े कागजी पुलिंदों पर सवार हो जाते है। लेकिन जिले की हकीकत इन कागजी पुलिंदों से कई अलग नजर आती है। नतीजा सबके सामने है कि, पिछले कई दशकों की सरकारी कवायदों के बाद भी आज जिले का शैक्षणिक स्तर निम्न से उठकर उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। इसके बहुत से अलग-अलग कारण है जिन पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। मगर जनजातीय कार्य विभाग और जिला प्रशासन का ''अपनी ढपली अपना ही राग'' है।

कहने को तो जिले में जनजातीय कार्य विभाग अलग से है। पिछले कई वर्षों से यह विभाग जिले में कार्य कर रहा है। इस विभाग को सरकार की ओर से बहुत बड़ा बजट भी प्राप्त होता है। लेकिन यह विभाग हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियां बटोरता दिखाई पड़ता है। जबकि जिले में शिक्षा का स्तर है कि ''नौ दिन चले अढ़ाई कोस'' साबित हो रहा है। आधुनिकता के इस दौर में जिले में संपूर्ण शिक्षा के विकल्प न के बराबर है। हाई स्कूल या हाई सैकेंडरी के बाद बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए जिले से बाहर निकलना ही पड़ता है। यह स्थिति आने वाले भविष्य में कब सुधरेगी इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

फिलहाल जिले में मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षा को ही लक्ष्य मानकर काम किया जा रहा है। जिले में यूं तो सैकड़ों शासकीय शैक्षणिक संस्थाएं है। जिनमें प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और हाई सैकेंडरी जैसी शैक्षणिक संस्थाएं शामिल है। इनमें से अधिकतर हिन्दी माध्यम की ही है। जिले की कुछ ही सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं ऐसी है जिनमें प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होती है। जबकि अधिकतर सरकारी स्कूलें हिन्दी माध्यम की ही है। इसी तरह जिले की लगभग सभी हाई स्कूल और हायर सैकेंडरी स्कूलें सिर्फ और सिर्फ हिन्दी माध्यम की ही है। विडम्बना यह कि, जिले में एक भी हाई स्कूल या हायर सैकेंडरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम की नहीं है। यह ओर बात है कि, हिन्दी माध्यम की हाई स्कूल और हायर सैकेंडरी स्कूलों में अंग्रेजी विषय जरूर होता है। मगर जिले में पूर्ण अंग्रेजी माध्यम की एक भी शासकीय हाई स्कूल या हायर सैकेंडरी स्कूल ना होना चिंता का विषय है।

हालांकि दावे अब भी बरकरार है। जिले में पिछले कुछ वर्षों में सीएम राईज जैसे स्कूलों की स्थापना हुई है। इन सीएम राईज स्कूलों को सांदीपनि नाम दिया गया है। सरकार का दावा यह है कि, इन स्कूलों में हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में निजी स्कूलों जैसी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, आधुनिक बुनियादी ढांचे और परिवहन सुविधाओं के साथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन सांदीपनि विद्यालयों का उद्देश्य यह है कि, गरीब वर्ग के छात्रों को भी विश्व स्तरीय और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान की जाए। इन संस्थाओं में भारतीय संस्कृति, कला, खेल और चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह स्कूल सर्वसुविधा युक्त, स्मार्ट क्लासेस और आधुनिक लैब से लैस होंगे। ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए स्कूल बसों की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। सरकार ने इस पहल के तहत राज्य भर में 370 से अधिक स्कूल विकसित किए है।

इनमें से जिले में भी कई स्कूल स्वीकृत हुए और उनका निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन जमीनी हकीकत से दूर वे अभी पूर्ण रूप से संचालित ही नही हो पा रहे है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा यह है कि, सीएम राईज स्कूलों की कक्षाएं शुरू कर दी गई है। नवीन भवन बनने के बाद इसे पूर्ण रूप से सही तरीके से संचालित किया जाएगा।

जिले में इन सांदीपनि स्कूलों की स्थिति अब तक तो कुछ खास नजर नहीं आ रही है। भवन जरूर बन चुके है लेकिन कई जगह अब भी निर्माण कार्य अधूरे ही है। कक्षाओं का संचालन हो रहा है लेकिन वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा सरकारी दावों में बताया जा रहा है। जिले में संचालित होने वाले सांदीपनि स्कूलों की स्थिति यह है कि, यहां कक्षाएं लग रही है लेकिन अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं नहीं सिर्फ हिन्दी माध्यम की कक्षाएं ही है।

कुछ सरकारी शिक्षकों से जब इस संबंध में बात की गई तो पता चला कि, स्कूल भवन बन चुके है लेकिन अंग्रेजी माध्यम तो कहीं भी नहीं है। कारण पूछने पर बताया कि, अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं तभी शुरू हो सकती है जब स्टॉफ हो और वर्तमान स्थिति में विभाग के पास ऐसा कोई स्टॉफ ही नहीं है, जो बच्चों को सभी विषयो में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान कर सके। पहले भी जिले में कोई अंग्रेजी माध्यम की हाई स्कूल या हायर सैकेंडरी स्कूल नहीं रही है। हालांकि कुछ प्राचार्यों ने अपने दम पर जिला मुख्यालय पर उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम की शुरूआत की थी। कुछ वर्ष इन अंग्रेजी माध्यम सैकेंडरी कक्षाओं का संचालन भी हुआ था। लेकिन बाद में विभाग ने अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की कमी के चलते इन कक्षाओं को 2018 में बंद कर दिया। तब से किसी भी शासकीय हायर सैकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम जिले में नहीं है।

सरकार ने जिस तरह के दावे और घोषणाएं सांदीपनि विद्यालयों को लेकर की है वह जिले में शायद दिवास्वप्न ही साबित हूआ है। क्योंकि सांदीपनि स्कूलों का संचालन तो शुरू हो चुका है लेकिन घोषणाओं में जिन सुविधाओं की उपलब्धता की बात कही गई थी वह पूरी तरह से नदारद ही नजर आ रही है। वर्तमान में ना अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई है, ना ही निजी स्कूलों वाली उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, ना ही ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था। मौजूद है तो सिर्फ आधे अधूरे भवन जो सीएम राईज स्कूल यानि सांदीपनि के नाम से है।

बात करें वर्तमान स्थिति की तो, अगर कोई पालक अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा हाई स्कूल या हायर सैकेंडरी स्कूल में दिलवाना चाहता है तो जिले में उसके पास कोई विकल्प नाम की चीज नही है। सरकारी आंकड़े भले ही कुछ भी दावे कर रहे हो लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है। पालक अपने बच्चों को अगर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना चाहते है तो फिर मजबूरीवश उन्हे आर्थिक शोषण का शिकार होते हुए निजी संस्थाओं की तरफ रूख करना ही पड़ेगा। जिले की आर्थिक स्थिति पर नजर डाले तो यह हर पालक के लिए इतना आसान तो नहीं है कि, वह निजी स्कूलों को हजारों रुपए की भारी भरकम फीस भर सके। नतीजा या तो बच्चे की शिक्षा का अंत या फिर पालक पर निजी स्कूलों की फीस का आर्थिक बोझ। दोनों ही स्थिति सरकार व जिला प्रशासन के शिक्षा को लेकर किए जा रहे दावों की हवा निकालती दिखाई दे रही है।

संकल्प से समाधान अभियान के समापन के साथ ही जिलेवासियों की सारी समस्याओं का समाधान हुआ पूरा...?

100 मे से 100 नंबर और राष्ट्रपति पुरूस्कार की सिफारिश यानि पूरा अभियान योजनाबद्ध प्रायोजित

माही की गूंज, झाबुआ।

लंबे समय के बाद जिले में प्रभारी मंत्री का आगमन कई सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। उस पर सितम यह कि, वे अपने दौरे के दौरान प्रशासन के ''संकल्प से समाधान'' अभियान को 100 में से 100 नंबर और कलेक्टर को राष्ट्रपति पुरूस्कार की सिफारिश का झुनझुना देकर चले गए। यह घटनाक्रम ही अपने आप में कई संदेह पैदा कर जाता है। प्रशासन का यह ''संकल्प से समाधान अभियान'' कुल मिलाकर 78 दिनो का रहा। जिसमें जिला प्रशासन के अनुसार 83,195 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 83,012 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा 100 में से 99.7 प्रतिशत बनता है। लेकिन जिले के प्रभारी मंत्री ने भरे मंच पर इस अभियान को लेकर प्रशासन को 100 में से 100 नंबर दे डाले। आयोजन में प्रभारी मंत्री के भाषण को सुनने पर साफ-साफ यह महसूस हो रहा था कि, किस तरह जिला प्रशासन ने प्रभारी मंत्री को बोतल में उतारा है। वे अभियान के समापन को बार-बार शुभारंभ बताते रहे। ऐसा तभी होता है जब कहानी पुरी तरह से प्रायोजित हो। हालांकि प्रभारी मंत्री विजय शाह की जुबान पर भी इतना भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे पहले भी बदजुबान ही रहे है और अपनी बदजुबानी के चलते मीडिया में सुर्खियों में रहे है।

मगर सवाल प्रशासन के इस प्रायोजित अभियान पर भी खड़े होते है जिसमें महज 78 दिनों में 83,012 आवेदनों का निराकरण कर दिया। जो यह दर्शाता है कि, औसत हर रोज प्रशासन ने 1065 आवेदनों का निराकरण किया। अगर यह हकीकत है तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर इसमें संदेह है क्योंकि जिले में सैकड़ों मामले जनसुनवाई में आते है और आवेदक का निराकरण नहीं हो पाता। जबकि आवेदक को अपनी सुनवाई और समाधान के लिए चप्पलें तक घिसनी पड़ जाती है। इस स्थिति में इस अभियान के दौरान प्रतिदिन लगभग 1065 आवेदनों का निराकरण सवाल तो खड़े करता ही है?? प्रशासन की स्थिति को अगर देखे तो ऐसा लगता है जैसे अब जिले में कोई समस्या ही नहीं है। सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। जबकि जो काम प्रशासन ने अभियान के तहत किया है वह तो जिला प्रशासन और अधिकारियों की रोज की नैतिक जिम्मेदारी है। जिन 83,012 आवेदनों का निराकरण प्रशासन इस अभियान के तहत दर्शा रहा है उसमें लगभग आधे मामले राजस्व विभाग के है जिसमें खसरा, खतौनी और नक्शा संबंधी आवेदनों का निराकरण किया गया है। इसे जिले की विडम्बना ही कहेंगे कि, राजस्व विभाग के तहत इस अभियान से पहले इतने मामले पैंडिंग पड़े हुए थे। यह भी संभव है कि, इनमें से कुछ मामले वर्षों पुराने हो, लेकिन अभियान के नाम पर इन्हे इसमें शामिल कर लिया गया हो। पुराने पेंडिंग मामलों का एक गुलदस्ता सजाकर इसे संकल्प से समाधान अभियान का नाम देकर प्रशासन और अधिकारियों ने थोथी वाहवाही लूटने के लिए इस पूरे आयोजन को अंजाम दिया हो। संदेह यह भी कि, अगर प्रशासन इस अभियान का स्वांग न रचता तो शायद जिले के प्रभारी मंत्री भी जिले में इस प्रवास के लिए नहीं आते। कुल मिलाकर यह सारा का सारा आयोजन प्रशासन द्वारा प्रायोजित ही नजर आ रहा है। अभियान के समापन अवसर पर पहुंचे प्रभारी का बार-बार समापन की जगह शुभारंभ कहना और 100 मे से 100 नंबर देना तथा राष्ट्रपति सम्मान के लिए सिफारिश करना इस अभियान के प्रयोजित होने का पुख्ता सबूत भी माना जा सकता है।

हालांकि प्रशासन के इस संकल्प से समाधान अभियान में राजस्व मामलों के मुकाबले अन्य विभागों के आवेदनों में भारी गिरावट भी कई सवाल खड़े करती है। अभियान के तहत सहकारिता विभाग में 6889 मामले, स्वास्थ्य विभाग संबंधी 5220, सामान्य प्रशासन से संबंधित 5794 मामले, इसके उलट राजस्व विभाग से संबंधित मामलों की संख्या 40,348। यह इतनी अधिक है कि, अन्य विभागीय मामलों के मुकाबले कई गुना है। यह स्थिति को इस तरह भी दर्शाता है कि, प्रशासन ने अभियान की 78 दिवसीय अवधी में समस्त विभागों में पेंडिंग पड़े आवेदनों को इकट्ठा किया और उनका निराकरण करते हुए वाहवाही लूटने की एक सटीक योजना तैयार की। इस तरह संकल्प से समाधान अभियान पूरा कर लिया गया।

ऐसा नहीं है कि, अब जिन विभागों को इस अभियान में शामिल किया गया था उनमें अब कोई शिकायती आवेदन पेंडिग नहीं होगा। मगर इस संबंध में जिला प्रशासन ने किसी तरह का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया। इस बात से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जब 78 दिनों की अवधी में इतने आवेदनों का निराकरण प्रशासन ने किया है तो फिर पेंडिंग आवेदनों की संख्या कितनी होगी...?

होना तो यह चाहिए था कि, प्रभारी मंत्री विजय शाह अभियान की भारी सफलता की जांच करते और हकीकत तक पहुंचते। उसके बाद फैसला करते कि, जिला प्रशासन को कितने नंबर देना चाहिए। मगर क्योंकि जिला प्रशासन ने अपनी चिड़ियां पहले ही बैठाकर प्रभारी मंत्री को बोतल में उतार लिया। नतीजा यह रहा कि, 100 मे से 100 नंबर देने के साथ ही उन्होने मंच से कलेक्टर के लिए राष्ट्रपति सम्मान के लिए सिफारिश करने का लालीपोप भी दे दिया।

बाकी रही जिले की समस्या तो प्रशासन के इस संकल्प से समाधान अभियान के बावजूद वह वहीं मुंह बाहे खड़ी है। जिले में पेयजल की समस्या जग जाहिर है। जिले के किसान पखवाड़े तक पेयजल समस्या के लिए धरना देते दिखाई दे रहे है। मगर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जिला प्रशासन ने खुद जिले को जलअभावग्रस्त घोषित कर दिया है। यह और बात है कि, जिला प्रशासन और कलेक्टर ने अपने इस अभियान में जिले की मूलभूत समस्या को शामिल ही नहीं किया। विडम्बना यह कि, खुद कलेक्टर ने जिले में भूमि क्रय -विक्रय को लेकर दी जाने वाली 165 की मंजूरियों को रोक रखा है और इसका आंकड़ा भी सैकड़ों में है। ऐसे ही और भी कई मामले है जो जिले व जिलेवासियों के अधर में लटके पड़े है। जिन्हे जिला प्रशासन ने अपने 'संकल्प से समाधान' अभियान में शामिल नहीं किया। क्योंकि जिला प्रशासन को तो सिर्फ अपनी थोथी वाहवाही से मतलब था, सो उन्होने जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह से करवा ली।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422